CNEWS सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-69
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, शुक्रवार, 14 जून 2024

आज का विचार

जो पुस्तकें सबसे अधिक सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया प्रस्ताव

नीट के 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स वापस, 23 को फिर से परीक्षा

नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 के 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स (कृपांक) देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प होगा कि वे फिर से परीक्षा देना चाहते हैं या बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट-यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा,

इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।

केंद्र ने कोर्ट से यह कहा

सरकार-एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1,563 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई, जिन्हें नीट-यूजी में शामिल होने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा का जिम्मा दिया गया। समिति ने 1,563 नीट-यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला लिया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। परीक्षाएं 23 जून को आयोजित की जाएंगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे।

कोर्ट ने एनटीए की दलील को रिकॉर्ड में लिया सर्वोच्च न्यायालय ने एनटीए के इस दलील को रिकॉर्ड में लिया कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा अधिसूचित की जाएगी और इसे संभवत: 23 जून को आयोजित किया जाएगा। परिणाम 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।

शिक्षा मंत्री बोले- किसी छात्र का नुकसान नहीं होने देंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। एनडीए में भ्रष्टाचार नहीं मिला है। यह बहुत विश्वसनीय निकाय है। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है और हम उनका आदेश मानेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी छात्र को नुकसान न हो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा में 24 लाख छात्र बैठे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह सुनवाई 1563 छात्रों के संबंध में है। सरकार कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार है। इस मुद्दे पर सरकार ने शैक्षिक जगत से जुड़े लोगों की एक समिति बनाई जा रही है। इस समिति की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनटीए ने देश में तीन बड़ी परीक्षाएं नीट, जेईई और सीयूईटी सफलतापूर्वक आयोजित कराई हैं। घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं छात्रों और उनके परिजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और एनटीए सभी प्रभावितों को न्याय दिलाएगी। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट की परीक्षा दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। न ही इसका कोई सबूत मिला है। 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा के लिए कोर्ट ने जो तरीका सुझाया है, उसके मुताबिक ही काम होगा और हम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करते हैं।

पॉक्सो केस में बीएस येदियुरप्पा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

गैर-जमानती वारंट जारी

बेंगलुरु। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट द्वारा वारंट ऐसे समय में जारी किया गया है जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को कहा था कि येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और अगर जरूरत पड़ी तो भाजपा नेता को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय एक लड़की की मां की शिकायत

के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि इस साल दो फरवरी को येदियुरप्पा ने यहां डॉलर कॉलोनी में अपने आवास पर मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। सदाशिवनगर थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटे बाद 14 मार्च को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक आदेश जारी कर मामले को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया था। येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी। येदियुरप्पा (81) ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि वह कानूनी तरीके से मामले में लड़ेंगे। उन्होंने अदालत से प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया है।

ऑनलाइन मंगवाई आइसक्रीम से निकली इंसान की उंगली

मुंबई। खाने की चीजों से कॉकरोच, छिपकली निकलने की घटना तो आपने बहुत बार सुनी और देखी होगी। लेकिन मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आइसक्रीम से इंसान की उंगली के मांस का टुकड़ा मिला है। घटना मुंबई के मलाड इलाके की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मलाड के रहने वाले डॉक्टर ओरलम ब्रैंडन सेराओ ने ऑनलाइन आइसक्रीम मंगवाई थी। उन्होंने बड़े चाव से आइक्रीम खोली लेकिन बाद में वे सन्न रह गए। उन्होंने फोटो को ऑनलाइन शेयर किया, जिसमें मांस का टुकड़ा बाहर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले लगा कि यह कोई अखरोट होगा लेकिन बाद में जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वह उंगली है। बता दें, डॉक्टर ने दोपहर में खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे थे तो कोन में से आधे इंच का एक मांस का टुकड़ा निकला, जिसमें नाखून भी था। वह फिलहाल स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने आइसक्रीम कंपनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसकी शिकायत

दर्ज कराई।

अखरोट समझ कर चबा रहा था

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि मैंने तीन आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाई थी। मैंने बटरस्कोच आइसक्रीम ली थी। मैं आइसक्रीम खा रहा था, तभी मुंह के अंदर कुछ ठोस चीज महसूस हुई। मुझे लगा कि यह अखरोट या चॉकलेट का टुकड़ा हो सकता है लेकिन मुझे मुंह में कुछ ज्यादा ही कड़ा महसूस हुआ। यह क्या यह जानने के लिए मैंने थूका तो मैं दंग रह गया क्योंकि यह अखरोट नहीं बल्कि इंसान की उंगली की मांस का टुकड़ा था। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूं तो मुझे समझ आ गया कि यह अंगूठा का हिस्सा है, इसमें नाखून दिख रहा था। मैंने तुरंत टुकड़े को आइसपैक में डाल दिया, जिससे पुलिस को दिखाया जा सके।

घटना की जांच कर रही है पुलिस

डॉक्टर ने आगे बताया कि मैंने मलाड पुलिस में घटना की जानकारी दी। मैंने आइसक्रीम ब्रांड के खिलाफ मिलावट और लोगों के जीवन को खतरे में डालने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आइसक्रीम को जांच के लिए और टुकड़े को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और यह भी तलाश रहे हैं कि आखिर आइसक्रीम में यह टुकड़ा आया कहां से।

तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए अजीत डोभाल

नई दिल्ली। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है और इसके साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालयों का आवंटन भी हो चुका है। गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। तब से डोभाल ही इस पद को संभाल रहे हैं। उनसे पहले शिवशंकर मेनन देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी अजीत डोभाल को कूटनीतिक सोच और काउंटर टेरेरिज्म का विशेषज्ञ माना जाता है। उधर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह जिम्मेदारी पीके मिश्रा ही संभालते रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अजीत डोभाल और पीके मिश्रा की पुनर्नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। आईएएस (सेवानिवृत्त) पीके मिश्रा को 10 जून 2024 से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। पीके मिश्रा 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह पिछले 1 दशक से प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। पीके मिश्रा प्रशासनिक मामले और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में नियुक्तियों का काम देखेंगे। इसके अलावा अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य मामले और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभालेंगे।

तीसरे कार्यकाल कीपहली विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी इटली रवाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए गुरुवार को इटली रवाना हो गए। यह प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा है। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी जी-7 से इतर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात कर सकते हैं। इटली में 15 जून तक आयोजित होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में संघर्ष का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। 15 जून तक इटली के पुगलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली गए हैं। पीएम मोदी 14 जून को आउटरीच सत्र में भाग लेंगे, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। मार्च 2023 में मेलोनी की भारत यात्रा के बाद पीएम मोदी की दूसरी बैठक होगी। यह यात्रा पीएम मोदी को शिखर सम्मेलन में मौजूद अन्य वैश्विक नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साऊथ के लिए अहम मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगी। जानकारी के अनुसार, शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। जी-7 शिखर सम्मेलन में भारतीय पीएम की भागीदारी से उन्हें पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर आगे की जाने वाली कार्रवाई करने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने की भी उम्मीद है।

26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार का गठन होने के साथ ही मंत्रियों को उनके मंत्रालय भी सौंप दिए गए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 18वीं लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? इस प्रश्न का उत्तर 26 जून को मिल जाएगा। दरअसल 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। उधर इस तरह की भी खबरें हैं कि राजस्थान की कोटा-बूंदी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले ओम बिड़ला को एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन डी पुरुंदेश्वरी के नाम पर भी चर्चा चल रही है।

मूवी पर विवाद-इस्लामिक मान्यताओं को गलत ढंग से दिखाने और मुस्लिम महिलाओं का गलत चित्रण करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नू कपूर फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगाई रोक

नई दिल्ली। फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है और उन्हें रचनात्मक लिहाज से कुछ छूट भी मिलती है। लेकिन 'हमारे बारह' मूवी की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि उच्च न्यायालय का आदेश आने तक इस फिल्म को रोक कर रखा जाए। मूवी के खिलाफ उच्च न्यायालय से लेकर शीर्ष अदालत तक अर्जी दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया कि यह फिल्म इस्लामिक मान्यताओं को गलत ढंग से दिखाती है। इसके अलावा विवाहित मुस्लिम महिलाओं का भी इसमें गलत चित्रण है। महिलाओं को लेकर इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे उन्हें कोई अधिकार ही नहीं हैं। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है, जिस पर ऐतराज है। फिल्म की स्टार कास्ट में अन्नू कपूर, मनोज जोशी और पारितोष त्रिपाठी हैं। फिल्म के लीड स्टार अन्नू कपूर ही हैं, जो मंजूर अली खान संजरी नाम के शख्स का रोल कर रहे हैं।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात

फिल्म की कहानी के अनुसार मंजूर अली की पत्नी प्रेग्नेंट होती है। इसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। महिला पहले भी कई बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, लेकिन पति मंजूर अली की जिद पर वह फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी सौतेली बेटी अलफिया से यह देखा नहीं जाता तो वह अदालत में मामला उठाती है। यह फिल्म मुस्लिम समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात करती है। इसके अलावा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम आजादी का सवाल भी

उठाया गया है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती आबादी और उससे होने वाली समस्याओं पर भी यह फिल्म बात करती है। इस फिल्म में ऐक्टिंग करने वाले मनोज जोशी कहते हैं, मैं तो एक कलाकार हूं। मैंने इस फिल्म में काम किया है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। मैं साफ कहूंगा कि यह फिल्म किसी धर्म को टारगेट नहीं करती।

मामले के निपटारे तक रिलीज पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा मामले के निपटारे तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। साथ ही हाई कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा है कि याचिका को तेजी से निपटाया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि बाम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका मे सीबीएफसी खुद पक्षकार है और उसकी ही कमेटी फिल्म की स्क्रीनिंग कैसे कर सकती है? याचिकाकर्ता का कहना था कि सीबीएफसी ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए एक कमेटी बनाई थी। सीबीएफसी की कमेटी ने स्क्रीनिंग के बाद उस फिल्म के टीजर और उससे जुड़े कुछ हिस्सों को हटाने का सुझाव दिया था। जिसको हटा लिया गया था और उसके बाद हाईकोर्ट में इस फिल्म की रिलीज की अनुमति दी थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

याचिकाकर्ता द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट मे दाखिल की गई याचिका मे कहा गया था कि यह फिल्म इस्लामी आस्था के खिलाफ और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने वाला है। फिल्म के कुछ डायलॉग्स पर भी आपत्ति जताई गई है।

अन्नू कपूर ने जारी किया था वीडियो

फिल्म का टीजर जारी होने के बाद अन्नू कपूर ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फिल्म को लेकर मचे विवाद पर प्रतिक्रिया दी थी। अन्नू कपूर ने अपने वीडियो में दावा किया था कि ये फिल्म सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। वीडियो में अभिनेता ने कहा था- यह फिल्म सिर्फ महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती है। आप सभी पहले फिल्म देखें और इसके बाद ही कोई धारणा बनाएं या अपना फैसला दें।

वेस्टर्न रिंग रोड के लिए अन्नपूर्णा क्षेत्र से हटाई अवैध चौपाटी

सिटी चीफ इंदौर।

नगर निगम और प्रशासन की टीम ने गुरुवार को अन्नपूर्णा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए। यहां अवैध चौपाटी भी बन चुकी थी। जिसे रिमूवल गैंग ने हटा दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अफसरों को व्यापारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। नगर निगम यहां पश्चिम रिंग रोड को जोड़ने वाली सड़क बनाएगा। जिसकी चौड़ाई 40 मीटर से ज्यादा है। इसमें 100 से ज्यादा निर्माण बाधक है। गुरुवार को रिमूवल गैंग के साथ प्रशासन और पुलिस के अफसर भी मौजूद थे। वे चौपाटी पर पहुंचे तो दुकानदारों ने अफसरों से कहा कि इस चौपाटी से उनका रोजगार जुड़ा है। क्षेत्र के रहवासियों के लिए भी यह एक सुविधा है। कम रुपयों में उन्हें सस्ते व्यजंन यहां मिलते है।

चौपाटी के नाम से पक्के निर्माण

अफसरों ने व्यापारियों से कहा कि चौपाटी के नाम पर शेड और पक्के निर्माण कर लिए गए। इसकी अनुमति भी नहीं ली गई। व्यापारियों ने थोड़े दिन की मोहलत देने की मांग की, लेकिन अफसर नहीं माने। इस दौरान एक व्यापारी ने अपने हाथ से ही खुद के गाल पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। दूसरे व्यापारियों ने उन्हें रोका। इसके बाद जेसीबी से अवैध निर्माण, गुमटियां हटाने का काम शुरू किया। अफसरों का सख्त रवैया देख दुकानों से सामान समेटना शुरू कर

दिया। इसके बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिए। अब नगर निगम इस हिस्से में सड़क बनाएगा।

पश्चिमी क्षेत्र के रिंग रोड की सर्विस रोड से भी हटेंगे कब्जे

पश्चिमी क्षेत्र के रिंग रोड के आसपास की सर्विस रोड को भी अतिक्रमणमुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। सर्विस रोड पर भी कई लोगों ने शेड व पक्के निर्माण कर सड़क का हिस्सा घेर लिया है। सड़क पर पार्किंग होने के कारण लोगों को वाहन चलाने में परेशानी होती है।

यह बोले मेयर पुष्यमित्र भार्गव

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि आचार संहिता हटने के बाद मास्टर प्लान की सड़कों के निर्माण के लिए अतिक्रमण हटाने का काम किया है। अन्नपूर्णा मंदिर- सुदामा नगर रोड में जितनी भी झुग्गियां थी, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्लैट दिए गए। उसके बाद जितने बाधक निर्माण थे, उन्हें हटाया गया है। शहर के विकास में यह महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में करीब 60 करोड़ की लागत से 25 मास्टर प्लान की सड़कों और निर्माण का काम जल्द एमआईसी में पारित करेंगे।

डीटीई ने जारी किया शेड्यूल

एमबीए-एमसीए कोर्स के लिए 2 जुलाई से ऑनलाइन काउंसिलिंग

इंदौर। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट (एमबीए) और मास्टर ऑफ कम्प्युटर साइंस (एमसीए) कोर्स में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट आफ टेक्नीकल एजुकेशन (डीटीई) ने ऑनलाइन काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। दोनों पाठ्यक्रम में 2 जुलाई से पंजीयन शुरू होंगे। पहले चरण में प्रवेश परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जा सकेगा। डीटीई ने प्रवेश प्रक्रिया संबंधित दिशा-निर्देश भी पोर्टल पर दिए है। विद्यार्थियों को 10वीं-12वीं व स्नातक अंतिम वर्ष की अंकसूची के अलावा प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड भी उपलोड करना होगा।

डीटीई के मुताबिक प्रदेशभर में एमबीए की 80 हजार और एमसीए में 30 हजार सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 76 कॉलेजों की 13 हजार विद्यार्थियों प्रवेश ले सकेंगे। जबकि एमसीए में 2 हजार सीटें है। विद्यार्थियों को दस दिनों का समय आवेदन करने के लिए दिया जाएगा।

पंजीयन की प्रक्रिया होने के बाद छात्र-छात्राएं अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की जाएगी। निजी कालेज संचालक संघ की पदाधिकारी डा. कविता कासलीवाल का कहना है कि दूसरे चरण से स्नातक उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

स्नातक में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में 95 हजार पंजीयन

सरकारी और निजी कॉलेजों से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे चरण में छह लाख सीटों के लिए गुरुवार शाम तक पंजीयन किए गए। अभी तक 95 हजार छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। दस्तावेज सत्यापन शुक्रवार तक करवाए जा सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक, पिछले चरण के मुकाबले इस बार 40 फीसद अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया है। दूसरा चरण होने के बाद कालेज स्तर पर विद्यार्थियों को सीएलसी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। बीए, बीकाम, बीएससी, बीजेएमसी, बीएसडब्ल्यू, बीएचएमसी, बीबीए, बीसीए सहित अन्य पाठ्यक्रम की छह लाख सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में 52 हजार छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था, जिसमें 41 हजार विद्यार्थियों को सीटें मिल चुकी है। दूसरे चरण में 27 मई से 13 जून तक पंजीयन के लिए विद्यार्थियों को समय दिया गया। 27 तक जमा करनी होगी फीस अधिकारियों के मुताबिक, प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बार मूल निवासी प्रमाण पत्र और एबीसी आइडी अनिवार्य कर दिया है। पिछले चरण में ज्यादातर विद्यार्थियों के पास मूल निवासी प्रमाणपत्र नहीं था। इस वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे। चुनाव की वजह से इनके प्रमाण पत्र बनने में समय लग रहा था। मगर अब मूल निवासी प्रमाणपत्र विद्यार्थियों को जारी होने लगे है। इसके बाद पंजीयन में तेजी देखने को मिली है।

गर्मी के बजाए बारिश में मालवा उत्सव कलाकरों ने भीगते हुए किया नृत्य

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। प्रदेश सरकार के सालाना आयोजन मालवा उत्सव मेले को इस बार इंदौर में मानसून सीजन में लगा दिया। उसका खामियाजा देशभर से आए कलाकारों और हस्थ शिल्पियों को उठाना पड़ रहा है। उत्सव के पहले दिन बारिश की भेंट चढ़ पाया। न ठीक से मंच पर प्रस्तुतियां हो सकी, न स्टॉल पर हस्तशिल्प बिके। अब बचे चार दिन अलग-अलग प्रांतों से आए लोगों को अपने उत्पाद बिकने की आस है। आमतौर पर मालवा उत्सव अप्रैल या मई माह में आयोजित होता रहा है। इसके लिए सांस्कृति विभाग, इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम से अनुदान मिलता है। इंदौर में मालवा उत्सव की कमान लोक संस्कृति मंच ने संभाल रखी है। इस मंच के कर्ता-धर्ता सांसद शंकर लालवानी खुद है। उनका कहना है कि आचार संहिता के कारण गर्मी के समय मेला नहीं

लग पाया। इसे जून माह में लगाया गया है। बारिश से बचने के इंतजाम भी किए गए है।

बिना प्रस्तुती दिए लौटे बाकी कलाकार

लालबाग पैलेस में लगे मालवा उत्सव के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति वाला मंच भव्य मंच बनाया गया है। बुधवार को उत्सव की औपचारिक शुरुआत की गई। इसके बाद गुजरात से आए कलाकारों ने सिद्धि धमाल नृत्य शुरू ही किया था कि बारिश शुरू हो गई। आधी-अधूरी प्रस्तुती देकर कलाकार मंच से उतर गए। बारिश आधे घंटे तक नहीं रुकी। इस बीच मंच की लाइट बंद कर दी गई। नृत्य देखने आए लोग भी बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भागने लगे। अपनी प्रस्तुती के इंतजार में अलग-अलग प्रांतों से आए कलाकारों को मायूस होकर लौटना पड़ा।

नारायण साईं की जमीन दिखाकर बीजेपी नेता से 40 लाख की ठगी

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। जेल में बंद नारायण साईं की जमीन दिखाकर भाजपा नेता से 40 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपी ने बाकायदा सौदे का एग्रीमेंट किया और नकद व चेक के माध्यम से रुपए ले लिए। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट पर खजराना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक खजराना निवासी दीनदयाल चौहान ने शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रापर्टी व्यवसायी दीनदयाल ने भाजपा नेता नासिर शाह(हबीब कालोनी) के साथ मिलकर ओमराव साबले (स्कीम-71) से ग्राम बिहाड़िया स्थित 19 बीघा जमीन का सौदा 9 करोड़ 11 लाख रुपए में किया था। नासिर शाह ने बेटे इरशाद शाह के नाम से अनुबंध किया और 11 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए। कुछ अन्य चेकों के माध्यम से भी 40 लाख रुपले लिए। जबकि जमीन राजस्व रिकार्ड में ओमराव के नाम से दर्ज ही नहीं थी। इस जमीन का कोर्ट में भी विवाद चल रहा है। मौके पर जाने पर पता चला भूमि पर कब्जा किसी और का है। इस जमीन का कुछ हिस्सा आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं, कल्पना, सूर्यकांत व रमेश पुराणिक के नाम पर है।

मामले की पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता को शिकायत की गई। गुप्ता ने क्राइम ब्रांच से जांच करवाई। जांच रिपोर्ट मिलने पर खजराना पुलिस ने को एफआइआर दर्ज कर ली।

आरोपियों ने मोबाइल बंद कर लिया

यह सौदा 14 दिसंबर 2023 को एग्रीमेंट पर हुआ था। जब पता चला कि जमीन बेचवाल की नहीं है तो पुलिस में केस दर्ज कराया। पुलिस ने दीनदयाल चौहान की शिकायत पर आरोपी ओमराव साबले निवासी स्कीम नंबर 71 इंदौर पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया जमीन ग्राम बिहाड़िया में स्थित है। जमीन की सच्चाई सामने आने पर रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने मोबाइल बंद कर लिया।

भरोसे में आकर सौदा कर लिया

फरियादी दीनदयाल चौहान ने पुलिस को बताया कि वह प्रॉपर्टी का काम करता है। उसने अपने दोस्त इरशाद पुत्र नासिर शाह के साथ मिलकर आरोपी ओमराव से जमीन का सौदा किया था। सौदा 9 करोड़ 11 लाख में तय हुआ। आरोपी साबले ने सौदे के वक्त बताया था कि यह जमीन उसी की है। अभी कोर्ट केस चल रहा है लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। भरोसे में आकर दीनदयाल ने इरशाद से चर्चा की और सौदा कर लिया। जब जमीन के सौदे के बाद खुलासा हुआ कि यह जमीन ओमराव साबले की है ही नहीं तो फरियादी दंग रह गया।

2013 से जेल में बंद है आसाराम का बेट नारायण साईं

2013 में सूरत की दो बहनों ने आरोप लगाया था कि आसाराम और नारायण साईं ने उनके साथ रेप किया है। दोनों बहनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साल 2002 और 2005 में बाप और बेटे ने उनको कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। दोनों बहनें आसाराम के आश्रम में साधक बनकर रह रही थीं। इस दौरान आसाराम और नारायण की पत्नियां ही उन्हें उनके पास ले जाया करती थी। इसके बाद दोनों बाप-बेटे उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते थे। रेप पीड़िताओं ने बताया था कि नारायण साईं उनको कई जगहों पर ले जाकर शारीरिक शोषण किया था। यहां तक कि अप्राकृतिक संबंध भी बनाया करता था। वो अक्सर ऐसा कई लड़कियों के साथ करता था। उसने कई लड़कियों से जिस्मानी रिश्ते बनाए थे। जब लड़कियों ने उसके खिलाफ रेप की शिकायत की तो वो कहता कि उनसे बहुत प्यार करता है। इतना ही नहीं उन्हें लव लेटर लिखकर अपने प्यार का इजहार भी किया करता था।

बगैर इजाजत पेड़ काटने पर जुर्माना नहीं, सीधे होगी एफआईआर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर नगर निगम अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पेड़-पौधों को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम उठाने जा रहा है। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए निगम प्रक्रिया को सख्त बनाएगा। पेड़ों को काटने की अनुमति अब आसानी से तो नहीं मिल पाएगी, वहीं इसके लिए शुल्क में भी कई गुना बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक निर्धारित नियमों के अनुसार, कोई भी अपनी जमीन पर लगे पेड़ को काटने के लिए एक हजार रुपये की रसीद कटवाकर अनुमति प्राप्त कर सकता है। इसे 10 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है यानी अब एक हजार रुपये के स्थान पर 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा। पेड़ काटने की अनुमति जारी करने से पहले निगम की टीम मौका-मुआयना भी करेगी। टीम को लगता है कि काटने के बजाय पेड़ को अन्यत्र ट्रांसप्लांट किया जा सकता है तो काटने की अनुमति देने के स्थान पर पेड़ों को ट्रांसप्लांट करवाया जाएगा। भू-स्वामी को इसके लिए निर्धारित खर्च उठाना होगा। ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। वहीं, बगैर अनुमति पेड़ काटने वालों पर सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा, उनके खिलाफ सीधे वृक्ष संरक्षण अधिनियम के प्रविधानों के तहत आपराधिक

प्रकरण भी दर्ज करवाया जाएगा। अपराध सिद्ध होने पर दो वर्ष तक के कारावास का प्रविधान है। नगर निगम ने नियमों में बदलाव के लिए प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे राज्य शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इंदौर शहर में चार दशक पहले तक हरियाली का प्रतिशत 30 से ज्यादा था, जो वर्तमान में 9 प्रतिशत के आसपास रह गया है। पर्यावरणविदों के अनुसार, ऑक्सीजन की आवश्यकता और कार्बन डाय ऑक्साइड के अवशोषण के हिसाब से एक व्यक्ति के लिए 8 से 10 पेड़ों की आवश्यकता होती है। शहर की जनसंख्या और घनत्व के हिसाब से यह संख्या करीब तीन करोड़ होती है।

इंदौर में होगी खेलो इंडिया वीमेन्स वेटलिफ्टिंग जोनल लीग प्रतियोगिता

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर महिला खेल एवं खिलाड़ियों के विकास हेतु अस्मिता खेलो इंडिया वीमेन्स वेटलिफ्टिंग जोनल लीग प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व भारतीय भारोत्तोलन संघ द्वारा मध्यप्रदेश को सौंपा गया है। प्रदेश वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा इस प्रतियोगिता को इंदौर में कराने का निर्णय लिया है। यह प्रतियोगिता 17 से 21 जून तक श्रीराम जिम्नेशियम रोबोट चौराहा, एमआर-9 पर होगी। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दविंदरसिंह खनूजा और सचिव डॉक्टर शरद नागर की सहमति से आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें दिनेश सोनगरा को अध्यक्ष और विपिन पाटीदार को सचिव नियुक्त किया गया है। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक महेंद्र हार्डिया, गौरव रणदिवे, सीबी होलकर हैं। संरक्षक विधायक गोलू शुक्ला, सभापति मुन्नालाल यादव, सावन सोनकर, राजेश उदावत, टीनू जैन, वीरेंद्र व्यास, राजाराम उस्ताद, जयपाल सिंह चावाड़ा और युनूस पटेल हैं। उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र पाटीदार, सतपाल सिंह खालसा, रामबाबू यादव, कालू गागोरे को नियुक्त किया गया है। संयुक्त सचिव गुड्डू कुमायू, अर्पित पालीवाल, दशरथ सिंह, कोषाध्यक्ष रईस पटेल होंगे। विधिक सलाहकार दुर्गेश शर्मा, चंद्रशेकर चौधरी, दिनेश चौहान, संजय कराड़े, मनीष पालीवाल होंगे। सत्कार समिति में महेश पालीवाल, सुरेश चौहान, शैलेंद्र प्रजापति, कोमलचंद पाटीदार, जयदीप पाटीदार, चंदू रावल, मनीष पहलवान, प्रचार समिति में राहुल जामोदिया, हर्ष जोशी, गजेंद्र राजपूत, ओम पाटीदार, गोविंद काकड़े, शंकर जोशी हैं। सदस्यों में योगराज पाटीदार, वीरसिंह चौहान, दिलीप भूरिया, अखिलेश मंडलोई, अभिषेक रावल, नितिन पाटीदार, सोनू सुमन, सोनू पहलवान, शिंकु ठाकुर, हर्ष जोशी, आकाश कौशल, पराग जैन, राजेश्वर वर्मा शामिल हैं।

विदेश में ड्रीम जॉब का झांसा देकर 18 लोगों से लाखों की ठगी, जांच शुरू

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। इंदौर में 18 छात्रों से करीब 12 लाख रुपए की ठगी हुई है। इंदौर क्राइम ब्रांच में लसूड़िया की रहने वाली पीड़ित महिला ने केस दर्ज कराया है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

दरअसल, फेसबुक पर विज्ञापन देखकर इंदौर की एक प्रोफेसर ने इंफिनिटी ग्रो साल्यूशन कंपनी के अनुज उर्फ नीरज कुमार शर्मा और सिमरन उर्फ वंदना वर्मा से मुलाकात की। उन्होंने झांसा दिया कि वह विदेश में नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। झांसे में आकर प्रोफेसर ने करीब 18 छात्रों से 12 लाख रुपए इकट्ठा कर आरोपियों को दे दिए। यह पैसा उन्होंने लॉकडाउन से पहले अनुज को दिए। पैसा मिलने के बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ता उससे मिलने चंडीगढ़ गई तो पता लगा कि उन्होंने ऑफिस भी खाली कर दिया है।

सोशल मीडिया में देखा विदेश में नौकरी का ऐड

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पीड़िता प्रोफेसर नेहा शर्मा ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। ये आरोपी पंजाब के अनुज उर्फ नीरज कुमार शर्मा और सिमरन उर्फ वंदना वर्मा है। नेहा ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में फेसबुक पर विदेश में नौकरी दिलाने का विज्ञापन देखा था। इसके बाद इंफिनिटी ग्रो साल्यूशन कंपनी के अनुज उर्फ नीरज कुमार शर्मा और सिमरन उर्फ वंदना वर्मा से खजराना क्षेत्र में मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों ने विदेश में नौकरी दिलाने का

भरोसा दिलाया। कहा कि वह चंडीगढ़ में इंफिनिटी ग्रो साल्यूशन में काम करती है। सिमरन ने नेहा से कहा कि यदि वह ऐसे और लोगों को लाती है जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उसे अच्छा कमीशन दिया जाएगा।

18 लोगों के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी

नेहा ने ऐसे 18 लोगों को अनुज उर्फ नीरज से मिलाया। सभी ने डॉक्यूमेंट के साथ फीस के रुप में करीब 12 लाख रुपए भी दिए। यह पैसा उन्होंने लॉकडाउन से पहले अनुज को दिया।

पैसा मिलने के बाद आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ता उससे मिलने चंडीगढ़ गई तो पता लगा कि उन्होंने ऑफिस भी खाली कर दिया है। करीब तीन साल तक नेहा उन्हें तलाशती रही। जब उनका कोई पता नहीं चला तो उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। बुधवार को क्राइम ब्रांच ने प्रोफेसर नेहा शर्मा की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ 419 और 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

सरकारी स्कूलों में दूसरी कक्षा के 66 प्रतिशत बच्चे नहीं पहचान पाते अक्षर

53 फीसदी को संख्या का ज्ञान नहीं

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। प्रदेश में निपुण भारत अभियान मिशन अंकुर के माध्यम से विद्यार्थियों की निपुणता में सकारात्मक प्रगति हुई है। रिपोर्ट में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवता में किए जा रहे सुधारों का असर दिखा है। यह बात गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने निपुण भारत अभियान मिशन अंकुर की कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही।

उन्होंने कहा कि यह परिणाम स्कूल शिक्षा विभाग के हर स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, लगन और परिश्रम का फल है। उन्होंने राज्य एवं जिलावार वार्षिक मूल्यांकन 2024 का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि नवंबर 2022 के मूल्यांकन के विगत रिपोर्ट कार्ड की तुलना में इस बार निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

दावे से उलट हकीकत

हालांकि 2024 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश के

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति यह है कि दूसरी कक्षा तक के 66 प्रतिशत बच्चे क, ग और ए, बी, सी, डी के अक्षर भी नहीं पहचान पाते हैं। इसी प्रकार 53 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो दो अंकों की संख्या भी नहीं पहचानते हैं। इसके बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग का दावा है कि वर्ष 2022 की अपेक्षा इस बार सरकारी स्कूलों में बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निपुण भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में मिशन अंकुर के नाम से इसे लागू किया गया है।

52 जिलों के 4500 स्कूलों में किया गया था सर्वे

अंकुर अभियान के तहत दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों में सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए 52 जिलों के 322 विकासखंडों में सर्वे किया गया। इसमें सैंपल सर्वे के लिए 4500 स्कूलों को चयन किया गया था, जिसमें दूसरी कक्षा के 34 हजार और तीसरी कक्षा के 37 हजार बच्चों को शामिल किया गया था। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन 2022 में किए गए सर्वे को आधार मानें तो इन कक्षाओं में काफी सुधार भी हुआ है।

51 प्रतिशत बच्चों को दो अंकों में घटाना नहीं आता

इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 51 प्रतिशत बच्चों को 20 तक की संख्या को घटना भी नहीं आता है। 25 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो दो अंकों की संख्या को जोड़ नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी कक्षा के 58 प्रतिशत बच्चे तीन शब्दों का वाक्य नहीं पढ़ पाते हैं। 66 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जिनको क, ख, ग पढ़ने नहीं आता है। वहीं तीसरी कक्षा के 40 प्रतिशत ऐसे बच्चे मिले, जिनको 99 तक के अंकों का जोड़ना-घटाना नहीं आता है। तीसरी कक्षा के 52 प्रतिशत बच्चे क, ख, ग, घ नहीं लिख पाते हैं। 57 प्रतिशत बच्चे वाक्य नहीं लिख पाते और न ही इनको पढ़ने में सक्षम हैं।

स्वजनों के तानों से परेशान नौवीं कक्षा की छात्रा ने लगाई फांसी

सिटी चीफ भोपाल।

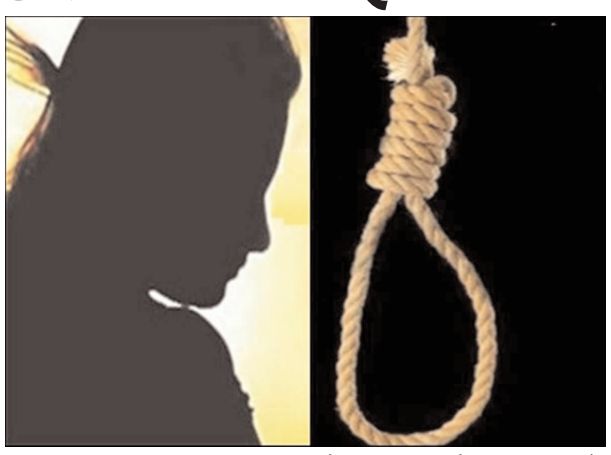

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के बरखेड़ा पठानी में रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी ने गुरुवार दोपहर करीब दो बजे अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। किशोरी नौवीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस को मृतका के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने जान देने का कारण अपने स्वजनों के रोजाना के घरेलू काम न करने को लेकर तानों को बताया है। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके आगे कुछ सपने हैं, लेकिन स्वजन उसे खाना बनाने और घर के काम करने को लेकर कहते हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गोविंदपुरा टीआइ अवधेश सिंह ने बताया कि इलाके के बरखेड़ा पठानी में परिवार के साथ रहने वाली निक्की आठवीं पास करके नौंवी कक्षा में पहुंची थी। घर पर उसकी एक बड़ी बहन और एक भाई हैं। उसके पिता आटो चलाते हैं। गुरुवार दोपहर में उसके स्वजनों ने उसे फांसी पर लटका देखा और पुलिस को सूचना दी। घटना के समय मां और पिता दोनों बाहर थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाकर पीएम के लिए भेजा दिया। बाद में घर की तलाशी लेने पर कमरे में एक कागज पर उसका सुसाइड नोट लिखा है। जिसका मजमून यह है कि वह आगे पढ़ना चाहती है,लेकिन उसके घर वाले उसे घर के काम करने के लिए कहते हैं, जिसमें उसका मन नहीं लगता है। घर वाले उसको लेकर उसे ताना मारते हैं। इन तानों से परेशान होकर यह कदम उठा रही है। उसने अपने इस कदम को लेकर किसी कोई भी परेशान न करने की बात भी कही है। पुलिस का कहना है कि मृतका के स्वजनों के बयानों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शीतलदास की बगिया में बंदरों का आतंक किशोर पर किया हमला

सिटी चीफ भोपाल।

पुराने शहर में बड़ी झील के किनारे स्थित शीतलदास की बगिया में उत्पाती बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां पर तीन से अधिक बंदर लोगों को प्रति दिन परेशान कर रहे हैं। इसकी जानकारी वन विभाग तक को है लेकिन वन अमले द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नतीजा यह रहा कि गुरुवार को परिवार के साथ घूमने आए किशोर पर बंदरों ने हमला कर दिया। यदि लोग उसे समय पर नहीं बचाते तो उसके साथ बड़ी घटना हो सकती थी। घायल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर उसे छुट्टी दे दी गई है।

नगर निगम के गोताखोर आसिफ ने बताया कि शिवपुरी का रहने वाला 12 वर्षीय अंकित अपने परिवार के साथ बड़ा तालाब स्थित शीतलदास की बगिया में घूमने आया था। वह सुबह 11 बजे बगिया में खेल रहा था, उसी वक्त एक बंदर ने आकर उस पर हमला कर दिया। वह संभलता इससे पहले ही बंदर ने उसके हाथ-पीठ में काट लिया। वह चीखा-चिल्लाया तो आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और उसे बंदर के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद किशोर के स्वजन उसे प्रोफेसर कालोनी स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया।

आसिफ ने बताया कि शीतलदास की बगिया में धार्मिक आयोजन होते हैं और लोग वोटिंग के लिए भी पहुंचते हैं। इसी जगह पर दो-तीन बंदरों ने आतंक मचा रखा है। वह पिछले एक महीने से आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसकी जानकारी कई बार वन विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक पकड़ने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

कांग्रेस और विधायक पद छोड़कर भाजपा में आए

कमलेश शाह को पार्टी ने बनाया अमरवाड़ा से उम्मीदवार

सिटी चीफ भोपाल।

कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर उपचुनाव होना है। कमलेश लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए थे। शाह लगातार तीन बार अमरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। अमरवाड़ा विधानसभा से भाजपा को लोकसभा चुनाव में 15 हजार 39 मतों की बढ़त मिली है। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष एकलव्य अहाके, जिपं सदस्य चंपालाल कुरचे, नवीन मरकाम और सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक रामनारायण परतेती के नाम पर विचार किया जा रहा है।

नकुल नाथ को लोकसभा चुनाव में अमरवाड़ा से लगा झटका

कमल नाथ के बेटे नकुल नाथ छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थे, उनके सामने भाजपा के विवेक बंटी साहू मैदान में थे। जानकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह द्वारा पार्टी और विधायक पद छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद नकुल नाथ को यहां बड़ा झटका लगा। इस विधासभा में भाजपा को वोटों में बढ़त भी मिली।

एक विधानसभा और एक राज्यसभा सीट पर भी होंगे उपचुनाव

मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट से विधायक शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद बनने के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। वहीं प्रदेश से राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ऐसे में शिवराज द्वारा बुधनी विधानसभा से और ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद इन दोनों पर उपचुनाव हो सकते हैं।

बुधनी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने जयवर्धन सिंह व शैलेंद्र पटेल को बनाया प्रभारी

बुधनी विधानसभा सीट से विधायक शिवराज सिंह चौहान के विदिशा संसदीय क्षेत्र से चुने जाने के बाद वे अब विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देंगे। इससे रिक्त होने वाली सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को प्रत्याशी चयन और पार्टी पदाधिकारियों के बीच समन्वय बनाने के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन कार्य प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जयवर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को प्रभारी बनाया है। दोनों नेता सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके जिले के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक करके सर्वसम्मति से संभावित प्रत्याशी का नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को देंगे, जिसे अंतिम निर्णय के लिए केंद्रीय संगठन को भेजा जाएगा।

मध्य प्रदेश में 18 जून तक आ सकता है मानसून, इंदौर, भोपाल जबलपुर, उज्जैन, सागर और शहडोल संभाग में बारिश के आसार

सिटी चीफ भोपाल।

दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले दो-तीन दिन में मानसून के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा में भी आगे बढ़ने के आसार हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 18 जून के आसपास मानसून के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर बनी चार मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्षा हो रही है।

इन संभागों में हो सकती है बारिश

इसी क्रम में गुरुवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक गुना में तीन मिलीमीटर वर्षा हुई। भोपाल में भी कहीं-कहीं बौछारें पड़ीं। प्रदेश में सबसे अधिक 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान सिंगरौली में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है।

ग्वालियर, रीवा संभाग में गर्मी

ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग के जिलों में अभी भी तपिश बरकरार रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के

आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। बिहार पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर नगालैंड तक एक द्रोणिका बनी हुई है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हवाओं का रुख दक्षिणी एवं दक्षिण-पश्चिमी बना हुआ है। हवा की रफ्तार भी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है। वातावरण में नमी रहने के कारण आंशिक बादल बने हुए हैं। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना कम है, लेकिन उमस बढ़ी हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, शहडोल, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग के जिलों में अभी तापमान बढ़ा ही रहेगा।

मोदी की जीत के लिए मांगी थी मन्नत, मां वैष्णो के दरबार में माथा टेकने निकले भोपाल के छह बाइक राइडर्स

भोपाल। लोकसभा चुनाव परिणाम और केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद आम लोगों के बीच राजनीतिक चर्चाएं थम गई हैं, लेकिन अपने पसंदीदा नेता को जिताने के लिए लोगों द्वारा मांगी गईं अनूठी मन्नतें अब चर्चाओं में हैं। भोपाल के एक राइडिंग क्लब के युवाओं ने भी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी की मन्नत मां वैष्णो देवी से मांगी थी। केंद्र में एक बार फिर मोदी सरकार के गठन के बाद उनकी मन्नत पूरी हो चुकी है और अब वे बाइक राइड कर मां वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने रवाना हो गए हैं। गुरुवार को शहर के छह राइडर आशीर्वाद दांडे, सागर जाचक, सतेंद्र, मनोज, ऋषि और विवेक 20 दिन की राइड पर भोपाल से रवाना हुए, जो जम्मू-कश्मीर के साथ ही मनाली और लेह-लद्दाख का टूर भी करेंगे। राइडर आशीर्वाद दांडे ने राइड पर जाने से पहले बताया कि चुनाव के दौरान हम छह दोस्तों ने चुनाव में मोदीजी की जीत की मन्नत मांगी थी और अब पूरी होने पर हम तीन बाइक से रवाना हो रहे हैं। यह राइड 20 दिन की रहेगी, जिसमें हम सबसे पहले दिल्ली पहुंचेंगे और वहां से चंडीगढ़ होते हुए सबसे पहले मनाली घूमेंगे। इसके बाद लद्दाख का एक स्पेशल टूर है, जिसमें हम उनके खान-पान और रहन-सहन सहित पूरे परिवेश को डाक्यूमेंटेड करेंगे। वहीं से हम पहले कश्मीर जाएंगे, जहां अति प्राचीन शारदा मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद जम्मू में जाकर माता वैष्णो देवी के दरबार पर मत्था टेकेंगे। यह राइड लगभग छह हजार किलोमीटर की रहेगी। हमें इस दौरान करीब 20 दिनों का समय लग जाएगा। इस दौरान हम जहां भी जाएंगे, वहां देश की एकता और भाईचारे का संदेश प्लेकार्ड के माध्यम से देंगे। आशीर्वाद ने बताया कि हम सभी राइडर्स अलग-अलग प्रोफेशन से हैं। मैं एक मैजिशियन हूं और कंटेंट क्रिएशन भी करता हूं। बाकि मेरे दोस्त कोई बिजनेस तो कोई नौकरी करता है, लेकिन राइडिंग हम सबको जोड़े रखती है। यह राइडिंग हम सिर्फ घूमने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि देश के उत्तरी भाग और वहां की संस्कृति को समझें।

पदवृद्धि की मांग को लेकर सड़क पर उतरे प्रतीक्षा सूची में शामिल शिक्षक

डीपीआइ के सामने किया प्रदर्शन

सिटी चीफ भोपाल।

उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) पात्रता परीक्षा 2023 की परीक्षा के प्रतीक्षा सूची में शामिल चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षकों की भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर गुरुवार को राजधानी की सड़क पर प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों की मांग है कि सरकारी स्कूलों में वर्ग-1 के जो पद खाली हैं, उनके विरुद्ध भर्तियां की जाए। उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में पदवृद्धि की मांग की, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके।

निकाला पैदल मार्च

प्रदेशभर से 700 से अधिक चयनित शिक्षक रानी कमलापति स्टेशन से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए बोर्ड आफिस चौराहे पर पहुंचे। इसके बाद संयुक्त मोर्चा (वेटिंग शिक्षक) के नेतृत्व में सुबह 10ः30 बजे से दोपहर दो बजे के बीच भाजपा कार्यालय से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) तक पैदल मार्च निकाला। डीपीआइ पहुंचकर धरना-प्रदर्शन किया। यहां काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। इस दौरान उमस और गर्मी के कारण दो महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गईं। आघा घंटा नारेबाजी करने के बाद पुलिस वालों ने चयनित शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। बताया गया कि सभी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने के लिए राजधानी में जुटे थे, लेकिन 3ः30 घंटे में ही यह आंदोलन खत्म हो गया। प्रदर्शन में शामिल महिला उम्मीदवार अपने साथ छोटे बच्चों को लेकर भी आई थीं।

अभी अनारक्षित श्रेणी में 102 लोगों को ही मिलेगा मौका

उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 8720 पदों पर भर्ती होना है। इनमें 3668 बैकलाग के पद हैं। आरक्षित सीट हटाने के बाद अनारक्षित श्रेणी के 102 पद ही बचते हैं। इसमें शिक्षकों की भर्ती विषयवार होना है। ऐसे में 102 पदों पर जब 16 विषयों में बांटा जाएगा तो अनारक्षित श्रेणी के छह से सात युवाओं को ही नौकरी मिल पाएगी।

34 हजार से अधिक पद खाली, नहीं हो रही नियुक्ति

चयनित शिक्षकों का कहना था कि सरकार ने 30 जुलाई 2018 के राजपत्र में स्वीकार किया है कि वर्ग-1 के 34,789 पद खाली हैं, लेकिन इतने पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। इनकी जगह पर 30 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इनकी जगह नियमित शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। सयुंक्त मोर्चा के नीरज द्विवेदी ने बताया कि हम लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी हमें वेटिंग में रखा गया है, जबकि हजारों पद खाली हैं। ऐसे में अतिथि शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए।

सम्पादकीय

अभी के प्रावधानों से राज्यों को विशेष दर्जा देना संभव नहीं

मोदी 3.0 सरकार पर उनके दो महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगियों बिहार से जदयू और आंध्रप्रदेश से टीडीपी का दबाव होगा कि वे उनके राज्यों को विशेष दर्जा दें। लेकिन मौजूदा प्रावधानों के तहत, राज्यों के लिए विशेष दर्जा देने का कोई नियम नहीं है।

केंद्र में गठबंधन सरकार बनने के साथ बिहार और आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों द्वारा विशेष दर्जे की मांग फिर से चर्चा में है। मोदी 3.0 सरकार पर उनके दो महत्वपूर्ण गठबंधन सहयोगियों बिहार से जदयू और आंध्रप्रदेश से टीडीपी का दबाव होगा कि वे उनके राज्यों को विशेष दर्जा दें। लेकिन मौजूदा प्रावधानों के तहत, राज्यों के लिए विशेष दर्जा देने का कोई नियम नहीं है। अगस्त 2014 में 13वें योजना आयोग के भंग होने के बाद से 14वें वित्त आयोग ने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया है। सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1 अप्रैल, 2015 से केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया और संसाधन अंतर का सामना करने वाले राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान का एक नया प्रावधान भी जोड़ा। नए प्रावधान के तहत, 2015-16 में राज्यों को कुल हस्तांतरण 2014-15 में 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.26 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 1.78 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि थी। राज्यों का हिस्सा जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूत्र द्वारा तय किया जाता है और प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के कर राजस्व को जुटाने का प्रयास करता है। यह फार्मूला भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र और राज्य की प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान में रखता है। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को संशोधित किया है और 2019 में जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए जाने के बाद इसे 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया है। इसलिए राज्यों को वर्तमान कर हस्तांतरण 2026 तक 41 प्रतिशत है। विशेष श्रेणी के दर्जे के तहत, जो मार्च 2015 तक लागू था, विशेष श्रेणी के राज्यों को सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय योगदान का 90 प्रतिशत मिल रहा था, राज्यों का योगदान केवल 10 प्रतिशत तक सीमित था। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को 2015 से पहले विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था। 90-10 का नियम अभी भी पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों पर लागू है, हालांकि कोई विशेष दर्जा श्रेणी नहीं है। अन्य सभी राज्यों को 60-40 के अनुपात में केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र सरकार का योगदान होता है और 40 प्रतिशत राज्यों का होता है। अगर मोदी 3.0 के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार इस दर्जे पर फिर से विचार करने और विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार और आंध्रप्रदेश की मांगों को पूरा करने का फैसला करती है, तो प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अरविंद पनगढ़िया के तहत 16 वें वित्त आयोग या नीति आयोग को भेजा जाना चाहिए। बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी ने राज्य में 135 सीटें जीती हैं।अब यहां नायडू ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग एक दशक से भी अधिक समय से की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के घोषणापत्र में आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। अब जब बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू और तेलुगू देशम पार्टी की जरूरत है तो उम्मीद है कि चंद्रबाबू राज्य को विशेष दर्जा देने की बड़ी मांग करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार के बिहार में भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठी है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को इस तरह की विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राज्य को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उसे यह दर्जा दिया गया था। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के सामने बिहार के लिए ये मांग रख सकते हैं, लेकिन विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए जो मानदंड है वे हैं- पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व और/या पर्याप्त जनजातीय आबादी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ इलाका। साथ ही राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होना, लेकिन बिहार और आंध्रप्रदेश के लिए ये मानदंड लागू नहीं होते हैं।

संसद में दागी नेताओं की संख्या बढ़ना चिंताजनक

आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं।

देश में 18वीं लोकसभा चुनी जा चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियां हैं वहीं चिंताजनक, विचलित एवं परेशान करने वाली स्थितियां भी हैं। खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है। भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना-हर नागरिक के माथे पर चिंता की लकीर लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतांत्रिक शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दागदार नेता एवं जन-प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों का विश्लेषण करने वाली सचेतक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में चुने गये सांसदों में जहां 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की थी, वहीं अठाहरवीं लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी बैठती है।

आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं। अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता आम चुनाव में कहते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि मैं जेल जाने से बच जाऊं। हम ऐसे चरित्रहीन एवं अपराधी तत्वों को जिम्मेदारी के पद देकर कैसे सुशासन एवं ईमानदार व्यवस्था स्थापित करेंगे? कैसे आम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? कैसे संसद में दागियों के पहुंचने के लिये द्वार बंद होंगे? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सजग पहल पर ही वर्ष 2020 से सभी राजनीतिक दल लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने लगे है। निश्चित ही इस आदेश का मकसद देश की राजनीति को आपराधिक छवि वाले नेताओं से मुक्त करना ही था। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की प्राथमिकता जीतने वाले उम्मीदवार थे, अब चाहे उनका आपराधिक रिकॉर्ड ही क्यों न हो। क्या हो गया उन लोगों को जिन्होंने सदैव ही हर कुर्बानी करके आदर्श उपस्थित किया। लाखों के लिए अनुकरणीय बने, आदर्श बने। चाहे आजादी की लड़ाई हो, देश की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, अपने वचन की रक्षा हो अथवा अपनी संस्कृति और अस्मिता की सुरक्षा का प्रश्न हो, उन्होंने फर्ज और वचन निभाने के लिए अपना सब कुछ होम दिया था। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, दुर्गादास, छत्रसाल, शिवाजी जैसे वीरों ने अपनी तथा अपने परिवार की सुख-सुविधा को गौण कर बड़ी कुर्बानी दी थी। गुरु गोविंदसिंह ने अपने दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया और पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों का तो मन्दिर बनना चाहिए। इनके मन्दिर नहीं बने, पर लोगों के सिर श्रद्धा से झुकते हैं, इनका नाम आते ही। लेकिन आज जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय जीवन और सोच विकृत हुए हैं, हमारी राजनीति स्वार्थी एवं संकीर्ण बनी है, हमारा व्यवहार झूठा हुआ है, चेहरों से ज्यादा नकाबें ओढ़ रखी हैं, उसने हमारे सभी मूल्यों को धराशायी कर दिया। राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश के भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापोह में हैं। वक्त आ गया है जब देश की संस्कृति, गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखर के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास करना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग के सामने नया मापदण्ड रखना होगा। अगर किसी हत्या, अपहरण या अन्य संगीन अपराधों में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसे राजनीतिक बता कर संरक्षण देने की कोशिश या राजनीतिक लाभ उठाने की कुचेष्ठा पर विराम लगाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त राजनीति को सदैव प्राथमिकता दी लेकिन चुनाव जीतने के रण में वे भी अपराधी राजनेताओं को प्रश्रय देते हुए दिखे हैं।

सभी राजनीतिक दलों ने ही दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जो राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के भारी अंतर को ही उजागर करता है। सवाल है कि देश के लिये नीति निर्धारण करने वाले ऐसे दागी लोग हमारे भाग्यविधाता बने रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद हमारी कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? क्या होगा हमारे समाज व व्यवस्था का भविष्य? क्यों तमाम आदर्शों की बात करने वाले और दूसरे दलों के नेताओं की कारगुजारियों पर सवाल उठाने वाले नेता राजनीति को अपराधियों के वर्चस्व से मुक्त कराने की ईमानदार पहल नहीं करते? क्यों सभी राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र में शुचिता एवं पवित्रता के लिये सहमति नहीं बनाते? निश्चित रूप से यदि समय रहते इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं होती तो आने वाले वर्षों में दागियों का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ ही बड़ा संकट यह भी है कि देश के निचले सदन में येन-केन-प्रकारेण करोड़पति बने नेताओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। इस बार संसद में चुनकर आए सांसदों में 504 करोड़पति हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवनयापन करने वाला आम आदमी कभी सांसद बनने की बात सोच सकता है? दागी एवं अपराधी राजनेता लोकतंत्र की एक बड़ी विडम्बना एवं विसंगति बनते जा रहे हैं। बात लोकसभा की ही नहीं है, विभिन्न राज्यों की सरकारों में भी कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक अपराध छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है, एक अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ होता है। यह कैसी विवशता है राजनीतिक दलों की? अक्सर राजनीति को अपराध मुक्त करने के दावे की हकीकत तब सामने आ जाती है जब किसी राज्य या केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन का मौका आता है। यह खुशी की बात है कि केन्द्र में बनी गठबंधन सरकार के मंत्रिमण्डल में ऐसी विवशता को काफी सीमा तक नियंत्रित किया गया है। सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा करने वालों की केवल एक ही मांग सुनने में आती है कि मरने के बाद हमारी लाश हमारे घर पहुंचा दी जाए। ऐसा जब पढ़ते तो हमारा मस्तक उन जवानों को सलाम करता है, लगता है कि देश भक्ति और कुबार्नी का माद्दा अभी तक मरा नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा आदर्श कब उपस्थित होगा। राजनीति में चरित्र एवं नैतिकता के दीये की रोशनी मन्द पड़ गई है, तेल डालना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के घरों पर सीबीआई के छापे और जेल की सलाखें हो या बिहार मंत्री परिषद के गठन में अपराधी तत्वों की ताजपोशी-ये गंभीर मसले हैं, जिन पर राजनीति में गहन बहस हो, राजनीति के शुद्धिकरण का सार्थक प्रयास हो, यह नया भारत -सशक्त भारत की प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए।

सभी अपनी-अपनी पहचान एवं स्वार्थपूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करते हैं। राजनीति की दशा इससे भी बदतर है कि यहां जनता के दिलों पर राज करने के लिये नेता अपराध, भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता का सहारा लेते हैं। जातिवाद, प्रांतवाद, साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर जनता को तोड़ने की कोशिशें होती है। पर हम कितना भ्रम पालते हैं। पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती। बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ न कुछ चाहिए। उसी प्रकार राजनीतिक चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल, साफ छवि, ईमानदारी एवं अपराध-मुक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीति में चरित्र-नैतिकता सम्पन्न नेता ही रेस्पेक्टेबल (सम्माननीय) हो और वही एक्सेप्टेबल (स्वीकार्य) हो।

सियासत से नहीं बुझेगी दिल्ली की प्यास, टैंकर माफिया के सामने बेबस है सरकार

वैसे तो मौसम की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को हर साल भीषण गर्मी के दौरान पानी की भारी कमी से जूझना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी दिल्ली के जल संकट के लिए कभी दिल्ली के उपराज्यपाल को, तो कभी हरियाणा सरकार को दोषी ठहराती रहीं, तो वहीं उपराज्यपाल जल संकट के लिए पानी की चोरी और बर्बादी को मुख्य कारण बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने टैंकर माफिया पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और यह भी माना है कि इसी वजह से यह समस्या इतना विकराल रूप ले पाई है। अब जब हिमाचल साफ कह चुका है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ा है कि उसके पास जल बंटवारे के जटिल मुद्दे के समाधान की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। सवाल यह भी है कि जब हरियाणा द्वारा दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है, तो दिल्ली पानी की किल्लत क्यों झेल रही है। दिल्ली वाले पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं, मारामारी करने पर क्यों उतारू हैं? असलियत में यह सिलसिला दिल्ली में आप की सरकार के अस्तित्व में आने के साथ से ही लगातार जारी है। दिल्ली को हरियाणा से कुल 1,050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। एक से 22 मई तक हरियाणा मुनक नहर के कैरियर लाइन नहर यानी सीएलसी में 719 क्यूसेक और दिल्ली सब ब्रांच यानी डीएसबी नहर में 350 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मतदान के दो से तीन दिन पहले इसे 91 क्यूसेक तक कम कर दिया गया। जहां तक मुनक नहर की मरम्मत और रख-रखाव का सवाल है, इसका ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ना नितांत गलत है, क्योंकि नहर की मरम्मत और उसके रख-रखाव का जिम्मा हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग का है। हकीकत में मुनक नहर से पानी बवाना लाया जाता है। बवाना से पहले यदि पानी की चोरी होती है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। यह तो रही दूसरे राज्यों से पानी आने, न आने की बात। कम पानी आने से वजीराबाद जलाशय का स्तर सामान्य से पांच फीट नीचे आ जाना खतरे का संकेत है। दिल्ली में जगह-जगह लोगों के लिए लगाए गए वाटर एटीएम की बात करें, जिसके बारे में भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के बढ़-चढ़कर दावे किए जा रहे थे, तो हकीकत यह है कि वे खराब पड़े हैं। जहां तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, तो हाल फिलहाल नौ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। दिसंबर तक द्वारका में एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा।

अपने ही बनाए नियमों को सुबह शाम तोड़ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री...और उनके मंत्री

बोलने की आजादी, जुझारू व हर तरह के सेंसरशिप से आजाद मीडिया, असहमति को सहन करने की ताकत, असंतोष को दबाना-ये सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम दुनिया भर में पढ़-सुन रहे हैं। हर जगह शासक और ताकतवर लोग मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं खबरों को प्रकाशित एवं प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जो उन्हें पसंद हों। दक्षिण एशिया के देश दुनिया के अन्य देशों से अलग नहीं हैं और इस हफ्ते मैं अमर उजाला के पाठकों का ध्यान इस खबर की ओर दिलाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो गई हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि मीडिया की आवाज को और दबाया जा सके। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को चुप कराने संबंधी खबरों में सबसे निराशाजनक खबर दिवंगत बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आई है, जिसने पंजाब प्रांत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की मरियम नवाज सरकार के नए विवादास्पद पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 को पारित कराने में साथ दिया है, ताकि उन आक्रोशित नागरिकों को शांत किया जा सके, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अतीत में जनरल जिया उल हक जैसे सैन्य तानाशाहों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी और विरोध करने वालों को सार्वजनिक रूप से कोड़े तक मारे थे। आज भी मेरे एक बुजुर्ग सहकर्मी नासिर जैदी जीवित हैं, जो बताते हैं कि कैसे तानाशाह ने उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने की हिम्मत करने के लिए कोड़ों से पीटा था। आज असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यही नहीं, अब पत्रकारों के गायब होने और उनकी हत्या का खतरनाक चलन भी दिख रहा है। इससे पहले दुनिया भर के तानाशाहों की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ महीने पहले पूरे पाकिस्तान में एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब लोगों को वीपीएन इंस्टाल करना पड़ता था, जो सिस्टम को अनब्लॉक करने में मदद करता है, ताकि उपयोगकर्ता ट्वीट कर सकें। इनमें से कुछ वीपीएन मुफ्त हैं, जबकि कुछ अन्य के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, तभी एक्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां आम लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। इस हफ्ते हम सबको इस बात पर हंसी आई कि एक्स को ब्लॉक किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री को आम चुनाव में जीत की बधाई ट्वीट करके दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके जवाब दिया। इस पाखंड को सबने समझ लिया कि पाकिस्तान के राजनेता कैसे अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब पंजाब प्रांत की सरकार ने पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 के लिए आधिकारिक रूप से गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे विवादास्पद कहा जाता है। नए कानून का उद्देश्य यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं से निपटना है, जिससे 'फर्जी खबर' फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सके। इस बात से हर कोई सहमत है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया जाता है, उनमें से कुछ नफरत से भरा और अस्वीकार्य होता है। लेकिन उन अकाउंट को बंद करने के बजाय, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप पूरे नेटवर्क को बंद नहीं कर सकते। पत्रकार समुदाय ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया है। गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से भी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण कड़ी आपत्ति जताई गई है। अंग्रेजी दैनिक द डॉन ने संपादकीय में लिखा है- %ये घटनाक्रम इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसे आम नागरिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। यहां चिंता यह नहीं है कि नागरिकों को जो कुछ भी वे कहना या उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें उसकी अनुमति दी जानी चाहिए, आखिरकार नागरिक होने के नाते वे भी देश के कानून से बंधे हैं। बल्कि डर यह है कि इन हथकंडों का इस्तेमाल पुलिस और सत्ता से असहमत केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। इस हफ्ते की दूसरी चौंकाने वाली खबर यह है कि शहबाज शरीफ सरकार अब इंटरनेट फायरवॉल बना रही है, जिसे कथित तौर पर अधिकारियों ने गुप्त रूप से लागू करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली या देखी जाने वाली हर चीज पर जासूसी करने की अनुमति देगा। यह इंटरनेट फायरवॉल ग्रेट फायरवॉल की तरह है, जिसका उपयोग चीनी अधिकारी अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए करते हैं। यह इंटरनेट फायरवॉल इंटरनेट पुलिस की तरह काम करेगा। खबरें बताती हैं कि सरकार ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे यह निगरानी की जा सकेगी कि कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट पर क्या कह, सुन या पढ़ रहा है। एक दृष्टिकोण है कि इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इस परियोजना के पूरा होने से पहले उचित मंचों पर इसे जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान तानाशाहों को अपने लोगों पर नियंत्रण बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के निरंतर प्रयासों पर पूर्व संपादक अब्बास नासिर ने कहा, %यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों मीडिया पर होने वाली किसी भी चर्चा में लगभग हमेशा पारंपरिक मीडिया को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन समाचार साइटों के अलावा, चौबीसों घंटे चलने वाले दर्जनों टीवी चैनल और समाचार पत्र। इसका केवल एक कारण हो सकता है = पारंपरिक मीडिया अब अधिकारियों के इतने अधीन है कि इसे बड़े पैमाने पर उनका मुखपत्र माना जाता है। बहुत कम सम्मानजनक अपवादों के बावजूद। अगर आप मुझसे पूछें, तो यह दुखद है।बहरहाल, कई दशकों के अपने अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर पलटवार करेगा। यहां तक कि अतीत में भी इसने सैन्य एवं असैन्य तानाशाही का विरोध किया है। हम अपनी जगह वापस पाने, अपनी आवाज बुलंद करने और सच बोलने के लिए लड़ेंगे।

मुझे काफी अपमानित महसूस हुआ...

सांसद बनीं कंगना रणौत ने राजनीति में एंट्री पर दिया ये बयान

बॉलीवुड क्वीन कंगना रणौत ने अपने सफल अभिनय करियर के बाद अब राजनीति में कदम रखा है। हाल ही में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से आम चुनाव जीता है। अभिनेत्री से सांसद बनीं कंगना रणौत ने हाल ही में ये स्पष्ट किया कि राजनीति में उनका प्रवेश 2020 की घटना का परिणाम नहीं है। 2020 में बृहन्मुंबई नगर निगम ने राय की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना के साथ उनके झगड़े के बीच उनके मुंबई स्थित घर के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। कंगना रणौत ने एक हिमाचली पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा, मुझे काफी अपमानित महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरे साथ बहुत हिंसा की गई है। एक घर आपका विस्तार है, लेकिन मेरा हिंसक रूप से टूट गया, यह उस समय एक व्यक्तिगत हमले की तरह लगा। उस घटना से मुझे यह पता चला कि महाराष्ट्र में कितने लोगों ने मेरा समर्थन किया और किस हद तक भारत ने मेरा समर्थन किया। अभिनेत्री ने कहा, शिवसेना की घटना को हर कोई जानता है और लोगों ने मुझे बताया है कि मैं साहसी हूं। उस घटना की एक खास फैन फॉलोइंग है। कंगना ने एक अन्य बातचीत में राजनीत में शामिल होने पर कहा, मुझसे 2019 में भी संपर्क किया गया था। अगर मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं होती, तो मुझे वास्तव में इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। कंगना रणौत के वर्कफ्रंट की बात करें तो जल्द ही वह फिल्म इमरजेंसी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। ये फिल्म 975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। इस फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े, सतीश कौशिक और महिमा चौधरी जैसे बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। यह फिल्म कई बार विलंबित हो चुकी है और इस साल सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है। इमरजेंसी की रिलीज का कंगना के फैंस को बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने इसे निर्देशित भी किया है। कंगना की निर्देशन में पहली फिल्म 2019 की ऐतिहासिक युद्ध ड्रामा मणिकर्णिका- द क्वीन ऑफ झाँसी थी, जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मुख्य भूमिका भी निभाई थी। कृष जगरलामुडी द्वारा सह-निर्देशित इस फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया।

नेटफ्लिक्स पर आज नहीं रिलीज होगी आमिर के बेटे की पहली फिल्म, प्रेस शो के बाद रिव्यू पर रोक

मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म के सात साल पहले की ये घटना है। जी हां, साल 1862 की। कानून के पुराने विद्यार्थियों से बात करेंगे तो वे बरसों पहले तक पाठ्यक्रम में शामिल रहे 'महाराज लिबेल केस' के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। किसी हिंदुस्तानी पत्रकार के खिलाफ दर्ज किया गया ये पहला मानहानि केस भी हो सकता है। मामला धर्म से जुड़ा है, इसलिए संवेदनशील है। और, देश के तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से चलाए जा रहे अभियानों का असर ये हुआ है कि कानून के पन्नों में दर्ज इस 'महाराज लिबेल केस' पर बनी फिल्म 'महाराज' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज नहीं हो रही है। जेम्स बॉन्ड बने डेनियल क्रेग का इस किरदार के रूप में उनका आखिरी संवाद याद है न, 'हिस्ट्री इजन्ट काइंड टू मेन हू प्ले गॉड!' ये संवाद यहां इसलिए ताकि सनद रहे कि मामला फिल्मी है और धर्म से जुड़ा तो कतई नहीं है। क्योंकि, दुनिया के हर धर्म में बस इसके 10 लक्षण हैं। इन 10 निर्देशों का अपनाने वाला ही धार्मिक हो सकता है, 'धृति- क्षमा दमोस्तेयं शौचम् इन्द्रिय निग्रह। धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षण।।' बापू के 'वैष्णव जन तो तेने कहिए' गाने से बरसों पहले गुजरात के एक युवक को समझ आया कि वैष्णव होना क्या है? और, क्यों सनातन संस्कृति को मानने वाले हर धार्मिक व्यक्ति का कृतित्व क्षत्रिय होने का और उद्देश्य शूद्र बन जाने का ही होना चाहिए। सौरभ शाह की लिखी पुस्तक 'महाराज' पर आधारित इसी नाम की फिल्म को लेकर सरगर्मियां काफी दिनों से चलती रही हैं। ये फिल्म बनी तो बड़े परदे के लिए ही थी, लेकिन फिल्म बनकर पूरी तैयार हुई तो इसे बनाने वाली कंपनी यशराज फिल्म्स और फिल्म से कैमरे के सामने अपना डेब्यू कर रहे जुनैद खान के पिता आमिर खान ने इस फिल्म को जब समग्र रूप से देखा तो दोनों ने इसे सिनेमाघरों में रिलीज न करने का फैसला लिया। फिल्म में जुनैद खान ने एक वैष्णव करसन दास का किरदार किया है जो इलाके के सबसे बड़े मठ के महाराज को उनकी करतूतों के चलते अदालत में घसीट लेता है। संयोग ही है कि जिस दिन आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म 'महाराज' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी, उसी दिन साउथ सिनेमा की एक फिल्म 'महाराजा' के नाम से अभिनेता विजय सेतुपति का टिकट खिड़की पर इम्तिहान लेने को तैयार हो रही है। विजय सेतुपति ने आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में उस समय काम करने से मना कर दिया था, जब उनकी फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था और अपनी फिल्म की लोकेशन तलाशने आमिर तुर्की हो आए थे। आमिर के बेटे जुनैद की एक और फिल्म अभिनेत्री साई पल्लवी के साथ शुरू हो चुकी है और उसके गाने भी आमिर अनौपचारिक मुलाकातों में लोगों को सुनाते रहे हैं। फिल्म 'महाराज' के प्रेस शोज बीते दिन यशराज फिल्म्स स्टूडियोज में बने थियेटर में हुए थे और मुंबई के तमाम फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को देखा भी था। फिल्म के रिव्यू लिखने पर शुक्रवार की दोपहर साढ़े बारह बजे तक की रोक थी लेकिन अब इन रिव्यू का प्रकाशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में पूछने पर यशराज फिल्म्स की प्रवक्ता ने बताया कि फिल्म 'महाराज' 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज नहीं होगी।

किल के ट्रेलर लॉन्च पर लगा सितारों का मेला, लक्ष्य लालवानी बोले- सपना पूरा होने में लग गए नौ साल

धर्मा प्रोडक्शन की नई फिल्म किल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म धर्मा के बाकी फिल्मों से काफी अलग है, क्योंकि इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म से लक्ष्य लालवानी अपना डेब्यू कर रहे हैं। ट्रेलर में कई बार उनकी झलक देखने को मिली है। किल के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में फिल्म से जुड़े कई लोग पधारे थे, इनमें करण जौहर, गुनीत मोंगा, अचिन जैन, लक्ष लालवानी, राघव जुयाल और तान्या मानिकतला शामिल थे।

किल का निर्देशन निखिल भट्ट ने किया है। उनके बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता करण जौहर ने कहा कि वो बहुत यादा शांत स्वभाव के हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। उन्हें देखकर लगता है कि वो एक मक्खी भी नहीं मार सकते। बता दें कि निखिल इससे पहले बृज मोहन अमर रहे, अपूर्वा और हुडदंग का भी निर्देशन कर चुके हैं।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष लालवानी ने कहा कि वो नौ साल से मुंबई में हैं। उनका सपना था कि एक दिन धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करेंगे और अब नौ साल बाद उनका सपना पूरा हो गया है। लक्ष्य ने करण जौहर और गुनीत मोंगा को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास फिलहाल कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं।

राघव जुयाल ने भी फिल्म में काम करने का मौका देने के लिए करण जौहर और गुनीत मोंगा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो तो मुंबई में ट्रेन पकड़कर डांसर बनने आए थे और अब फिल्मों में काम करने का अवसर मिल रहा है तो उनके लिए तो यह बोनस की तरह है। वहीं, फिल्म में मुख्य महिला किरदार निभा रही अभिनेत्री तान्या मानिकतला ने बताया कि फिल्म की कहानी पढ़ते ही उनका उत्साह बढ़ गया था। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनका पहला ही सवाल यह था कि फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी।

फिल्म में नहीं हैं, लेकिन फरदीन खान ने पढ़ ली नो एंट्री 2 की कहानी

बोले- इसे खराब मत कर देना

अनीस बमी की हिट फिल्म नो एंट्री का सीक्वल जल्द ही आने वाला है। यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी। इसमें सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, बिपाशा बसु और बोमन ईरानी समेत कई कलाकारों ने काम किया था। जबकि नो एंट्री 2 में दर्शकों को नए कलाकार देखने को मिलेंगे। इनमें वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर शामिल हैं। अब इस मामले को लेकर फरदीन खान ने अपनी बात रखी है।

2014-15 से चल रही है नो एंट्री 2 की चर्चाफरदीन खान ने हाल ही में, लंबे समय के बाद संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरामंडी से वापसी की है। एक हालिया साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि नो एंट्री 2 की चर्चा 2014-15 के वक्त से चल रही है। वो खुद भी इस प्रोजेक्ट को लेकर सलमान खान और बोनी कपूर के संपर्क में थे। सभी लोग फिल्म के दूसरे भाग को बनाने के लिए उत्साहित थे।

फरदीन को मजेदार लगी कहानी फरदीन खान अब सीक्वल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस फिल्म की कहानी जरूर पढ़ी है। उन्होंने बताया कि उन्हें कहानी मजेदार लगी है, जिसे पढ़ते ही वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाए थे। फरदीन ने अनीस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने एक कमाल की कहानी लिखी है। **फरदीन ने दी यह चेतावनी** फरदीन खान ने कहा कि उन्हें नो एंट्री 2 के नए कलाकारों से प्यार है। फरदीन ने उन्हें शुभकामना देने के साथ-साथ एक सलाह भी दे डाली। उन्होंने कहा कि नो एंट्री एक अच्छी फ्रेंचाइजी है, बस इसे खराब मत करना। ऐसा हुआ तो वो परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, नो एंट्री 2 की शूटिंग दिसंबर 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है, जो अगले साल जून तक पूरी हो सकती है।

टूटे हुए दिलों के लिए मरहम है जुबिन की आवाज, अपने सुरों के जादू से सजाए हैं कई रोमांटिक गाने

जुबिन नौटियाल आज बॉलीवुड में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक रोमांटिक गानों को अपने सुरों से सजाया है। आज जादुई आवाज के मालिक जुबिन नौटियाल अपना जन्मदिन मना रहे हैं। चलिए जुबिन के जन्मदिन पर हम आपको उनके करियर और लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं--

जुबिन नौटियाल के गाने टूटे दिलों पर महरम का काम करते हैं। उनके कई चाहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि जुबिन के गाने सुनकर प्यार के दर्द को वे लोग भी महसूस कर लेते हैं जिन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया हो। ऐसी मीठी आवाज के मालिक जुबिन का जन्म 14 जून, 1989 को उत्तराखंड के देहरादून शहर में हुआ था। वे बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे।

जुबिन नौटियाल ने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' से किया था, लेकिन वे इस शो के विजेता बनने से चुक गए। जुबिन ने इसके बाद कई और शो में भी भाग लिया लिया, लेकिन उनके किस्मत का तारा सोनाली केबल में गाए गाने इक मुलाकात हो से चमका था। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

जुबिन नौटियाल ने कई फिल्मों को अपने गानों के दम पर हिट करवाया है। सोनाली केवल के बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म जबा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। इस फिल्म का गाना बंदेया आज भी युवाओं की पहली पसंद है।

जुबिन नौटियाल ने कई फिल्मों को अपने गानों के दम पर हिट करवाया है। सोनाली केवल के बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म जबा में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा था। इस फिल्म का गाना बंदेया आज भी युवाओं की पहली पसंद है।

34 की उम्र में सुशांत ने किया था सुसाइड, टीवी से की थी अभिनय की शुरुआत

सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वह चेहरा हैं, जिसे कोई भुला नहीं सकता। सुशांत के जाने के बाद उनके परिवार, रिश्तेदार और यहां तक की उनके प्रशंसक भी उन्हें अक्सर याद करते रहते हैं। सुशांत ने अपने अभिनय से हर किसी का दिल इस कदर जीता, कि जब वह इस दुनिया से गए तो हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। सुशांत की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 14 जून 2020 की वो दोपहर जब सुशांत सिंह के निधन की खबर आई और पूरे देश में खलबली मच गई थी। आज सुशांत की पुण्यतिथि पर जानिए उनसे जुड़ी कुछ बातें।

टीवी से की थी अभिनय की शुरुआत और फिल्मी करियर

सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की थी। उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल 2008 में आया था, उसके बाद जी टीवी के लोकप्रिय शो पवित्र रिश्ता से उन्हें काफी प्रसिद्धी मिली थी। फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में आई फिल्म काय पो छे से की थी। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी में काम किया। 2016 की फिल्म एम. एस. धोनी- द अनटॉल्ड स्टोरी में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे सभी से पसंद किया था।

34 वर्ष की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को हो गया था। सुशांत का शव मुंबई के बांद्रा में स्थित फ्टैल में मिला था। मुंबई पुलिस ने सुशांत के निधन का कारण सुसाइड बताया था लेकिन सुशांत की फैमिली ने कहा कि उनका मर्डर हुआ है या फिर सुशांत को ऐसा करने पर मजबूर किया गया। जब फैंस और फैमिली की भारी डिमांड सरकार से हुई तो सरकार ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई अभी इसकी जांच कर ही रही थी तो ये केस एनसीबी की तरफ मुड़ गया। इसके बाद सबूत के आधार पर एनसीबी ने कई सेलिब्रिटीज से पूछताछ की। सुशांत के केस में फाइनली क्या हुआ अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है। सुशांत की फैमिली और फैंस आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं।

सतना में बजरंग दल ने तीर्थ यात्रियों पर हमले के विरोध में किया प्रदर्शन

बजरंग दल व विहिप के सैकड़ों कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे

सिटी चीफ। उमेश कुशवाहा।
सतना, बजरंग दल के द्वारा जमू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में पुतला दहन कर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सर्किट हाउस चौराहे में कफी संया में बजरंग दल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। हमले को लेकर काफी विरोध जताया। इस दौरान विहिप प्रान्त सह मंत्री सागर गुप्ता, विहिप जिलाध्यक्ष लखन केसरवनी, विक्रम चौधरी, बजरंग दल प्रान्त संयोजक यतेंद्र पाठक, सचिन शुक्ला, रावेन्द्र सिंह, बैजनाथ

त्रिपाठी, रमेश मिश्रा, अरुण पाण्डेय,बजरंग दल विभाग सह संयोजक अबीर द्विवेदी, सत्यप्रकाश, मुकेश गौतम, राजा सिंह, मनीष शर्मा, दिलीप त्रिपाठी, विकाश शुक्ला, ऋषभ शुक्ला व अन्य लोग मौजूद रहे। विहिप प्रान्त सह मंत्री सागर गुप्ता, बजरंग दल प्रान्त संयोजक यतेंद्र पाठक, विहिप जिलाध्यक्ष लखन केसरवनी, जिला सह मंत्री रावेन्द्र सिंह,विक्रम चौधरी, सचिन शुक्ला, बैजनाथ त्रिपाठी, रमेश मिश्रा, अरुण पाण्डेय, बजरंग दल विभाग सह संयोजक अबीर द्विवेदी, सत्यप्रकाश, मुकेश गौतम, राजा सिंह, मनीष शर्मा, दिलीप त्रिपाठी, विकाश शुक्ला, ऋषभ शुक्ला, श्री निवासी कचर, राकेश तिवारी, आदर्श त्रिपाठी, बदल चतुर्वेदी, राम सरण सिंह, छोटू उर्मलिया,धनंजय चतुर्वेदी, निशा जायसवाल, ममता खरे, मिथलेश तिवारी, प्रेमलता द्विवेदी, मंजू श्रीवास्तव, रीता त्रिपाठी, एवं सैकड़ों कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे.

कटनी में महिला थाना प्रभारी मधु पटेल थाने से हटाकर पुलिस लाइन में पदस्थ करा

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया एक्शन

सुनील यादव। सिटी चीफ।
कटनी, हमेशा विवादों में रहने वाली कटनी महिला थाना प्रभारी मधु पटेल को आज शाम पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने थाने से हटाकर पुलिस लाइन में पदस्थ कर दिया है। महिला थाना प्रभारी मधु पटेल की जगह उप निरीक्षक रश्मि सोनकर को महिला थाना

प्रभारी का प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दे की रश्मि सोनकर विशेष किशोर पुलिस इकाई में अब तक पदस्थ रही। आपको बता दे की पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा महिला थाना प्रभारी की लगातार शिकायत मिलने के कारण उनके ऊपर जांच भी शुरू कराई थी जिसके बाद करवाई देखने को मिली।

स्टेशन से अगवा कर किशोरी से गैंगरेप के एक आरोपी को जेल

मामले का दूसरा आरोपी अभी भी फरार

सिटी चीफ। उमेश कुशवाहा।
सतना, रेलवे स्टेशन से सीधी की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी को अगवा कर गैंपरेप करने वाले दो आरोपियों में से एक को रेल पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया है। आरोपी आटो चालक नवीन उर्फ नितिन गुप्ता 25 वर्ष पिता प्रशांत कुमार गुप्ता नागौद थाना इलाके के इटमा वीरपुर का रहने वाला है। वह सतना में शिवनगर पतेरी तलैया के पास राकेश बागरी के किराए के मकान में रहता है। वहीं मामले का दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है जिसको चिन्हित कर जीआरपी गिरफ्तारी के लिए संभावित अड्डों में दबिश दे रही है। जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राज ने बताया कि किशारी करीब एक माह पहले अपनी बुआके साथ सीधी से मुम्बई गई थी। वहां से पांच-छह

दिन पहले फूफा ने सीधी जाने के लिये अकेले ट्रेन में बैठा दिया था। लड़की 7 जून को सतना आ गई। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड जाने के लिए आरोपी गुप्ता के आटो में बैठ गई। आरोपी उसे बहला-फुसलकाकर पतेरी ले गया। फिर बाइक से उसे मैहर घुमाने ले गया और लौटते समय भटनवारा के पास दुष्कर्म किया। आठ जून को लड़की को स्टेशन के बाहर छोड़कर फरार हो गया था। स्टेशन से फिर आरोपी का साथी 20-22 वर्ष का पतला-दुबला लड़का बाइक से किशोरी को जैतवारा तरफ ले गया और दुष्कर्म करने के बाद आधी रात लड़की को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया था। पीड़िता रात दो बजे एक गांव पहुंची सिजके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना जैतवारा पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज से धराया आरोपी आरोपी गुप्ता सोमवार को ही जीआरपी के हत्थे चढ़ गया था। दरअसल, वारदात की सूचना मिलने के बाद से जीआरपी ने स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरु कर दी थी। आरोपी गुप्ता स्टेशन से बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में पहले आटो से ले जाते दिखा फिर वह सर्किट हाउस व सिविल लाइन में लगे कैमरों में कैद हुआ था। जब वह किशोरी को छोड़ने आया था तब भी कैमरे में कैद हुआ था। दूसरा आरोपी भी किशोरी को ले जाते कैमरे कैद हुआ था।

नर्मदापुरम से शादी करने अमरपाटन आया था युवक, शादी से पहले लड़की ने ऐंठ लिए डेढ़ लाख

लुटेरी दुल्हन गिरोह: शादी के बाद दूल्हे को रास्ते से छोड़कर भागी दुल्हन पुलिस को शिकायत में नहीं मिला दम, 151 की कार्रवाई

सिटी चीफ। उमेश कुशवाहा।
सतना, शादी के फेरों में सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली दुल्हन विवाह सपन्न होने के बाद सात किमी तक पति के साथ नहीं चल पाई। मैहर जिले के अमरपाटन में फिल्मी स्टाइल में फर्जी शादी कराकर दुल्हन अपनी गैंग के साथ फरार हो गई। लड़की की नानी की बीमारी का बहाना और शादी में खर्च लगने की बात पर दूल्हे से पहले ही डेढ़ लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। रास्ते से पत्नी के भागने के बाद पति थाने पहुंचा और अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने ठगी का केस दर्ज नहीं किया है। शादी और फिर दुल्हन के भागने की घटना मंगलवार की है। यहां गिरोह ने साजिश के साथ नर्मदापुरम के एक युवक से शादी का नाटक किया इसके बाद पूरा गिरोह दुल्हन को रास्ते से गाड़ी से उतार कर गायब हो गया। पुलिस को दी शिकायत में पिपरिया नर्मदापुरम निवासी सुजान सिंह ने बताया कि बनखेड़ी के रहने वाला इंदर पटेल की ससुराल अमरपाटन में है। इंदर ने फोन कर छोटे भाई रघुवीर की शादी के लिए लड़की देखा और सभी को अमरपाटन बुलाया। सुजान अपने भाई रघुवीर को लेकर 9 जून को अमरपाटन पहुंचा जिन्हें लल्लू कोल के घर पर

रुकवाया गया। वहीं लड़की को बुलाया गया और रामविश्वास कोल व अजय पटेल को उसका भाई बताया गया। कुछ और फर्जी रिश्तेदार बुलाकर इसके बाद बड़ा तालाब मंदिर में शादी कराई गई। इस तरह लगाया चूना रघुवीर की शादी फोन से टिकुरिया टोला निवासी अनीता पाण्डेय नाम की लड़की से तय की गई थी। मामले में कल्लू कोल और रामेश्वर पटेल ने मध्यस्थता की थी। आठ दिन पहले दोनों पक्षों में शादी की बात हुई, लेकिन लड़की पक्ष ने यह कहते हुए मना कर दिया कि दूर बहुत है। जिसके बाद दूल्हे के बड़े भाई ने उन्हें आने-जाने का खर्च देने को कहा। इसके बाद शादी-व्याह का डेढ़ लाख खर्च दिया। हनुमान मंदिर में शादी की रश्म अदा की गई। विदाई कर जब सभी लौट रहे थे तभी उन्हें जीप सवार कुछ लोगों ने रोक लिया। पुलिस होने का हवाला देते हुए दूल्हा-दुल्हन को वाहन में बैठा लिया। कुछ दूरी पर दूल्हे को उतार दिया और युवती को साथ ले गए। शादी के नाम पर ठगी और फेरों के बाद दुल्हन के भाग जाने की शिकायत के बावजूद पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज नहीं किया। टीआई अमरपाटन केपी त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद के चलते दुल्हन पति के साथ नहीं गई। थाना में आकर आपस में लड़ाई-झगड़ा करने पर दूल्हा रघुवीर पटेल पिता मारुलाल 33 वर्ष सेमरी कला थाना पिपरिया जिला नर्मदापुर, इंदर पटेल पिता मोहन निवासी बनखेड़ी नर्मदापुरम व रामविश्वास कोल पिता दीनबंधु 53 वर्ष जरमोहरा अमरपाटन के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। टीआइ ने बताया कि मामले की जांच जारी है। युवती को तलाश रहे हैं। उसका नाम व पहचान फर्जी हो सकता है। उसके मिलने के बाद ही मामला साफ होगा।

सहारनपुर में बजरंग दल ने बस पर हुए आतंकी हमले पर कड़ा रोष व्यक्त करते आतंकवाद का पुतला फूंका

राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाने की मांग की

गौरव सिंघल। सिटी चीफ।
सहारनपुर। देवबंद, बजरंग दल ने श्रद्धालुओं को लेकर वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी जा रही
बस पर हुए आतंकी हमले पर कड़ा रोष व्यक्त करते आतंकवाद का पुतला फूंका और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाने की मांग की। बजरंग दल के विभाग संयोजक मोकिंत राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जीटी रोड पर आतंकवाद का पुतला आग के हवाले किया। इसके उपरांत एसडीएम अंकुर वर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा। जिसमें कहा गया है कि 9 जून को वैष्णो देवी कटरा सेशिवखोड़ी जाते हुए श्रद्धालुओं

की बस पर हुए आतंकी हमले में 10 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए। इस घटना से संपूर्ण देशवासी स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर लंबे समय से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का दंश झेल रहा है। धारा 370 हटने के बाद भी आतंकवादी हिंदुओं को चिन्हित कर उनकी हत्याएं कर रहे हैं। बजरंग दल मारे गए तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और मृतक परिजनों को उचित मुआवजा और घायलों को बेहतर उपचार मुहैया कराए जाने की मांग करता है। ज्ञापन देने वालों में दिग्विजय शर्मा, शुभम शर्मा, पंकज सैनी, राजन, विशाल सैनी, विक्रांत, जयंत, अतुल, नितिन आदि मौजूद रहे।

देवबंद में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान टीम ने अतिक्रमण हटवाते हुए अतिक्रमणकारियों से 32 सौ रुपये का अर्थदंड भी वसूला

गौरव सिंघल। सिटी चीफ।
सहारनपुर। देवबंद, देवबंद नगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत अतिक्रमण हटाओ टीम ने कई स्थानों से अतिक्रमण हटवाते हुए अतिक्रमणकारियों से 32 सौ रुपये का अर्थदंड भी वसूला।पालिका की टीम ने पुलिस को साथ लेकर स्टेट हाईवे के किनारे एसडीएम कोर्ट से मंगलौर चौकी तक अतिक्रमण

हटवाते हुए 32 सौ रुपये का चालान भी किया साथ ही पालिका की टीम ने पुनः अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पालिका प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान से अतिक्रमणकारियों में हडकम्प मचा रहा। पालिका प्रशासन की टीम में अभियान के प्रभारी विकास चौधरी, एसआई पोपिन कुमार, सुंदर लाल, मोहम्मद ताबिश, अकबर बाबू आदि मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने 15 जून से आरम्भ हो रहे योग सप्ताह के सफल क्रियान्वयन के लिए की बैठक

21 जून को जनपद में भव्यता के साथ मनाया जाएगा योग दिवस

गौरव सिंघल। सिटी चीफ।
सहारनपुर, जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में दसवें अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2024 को धूमधाम से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने के सबंध में बैठक आहूत की गई। योग सप्ताह 15 जून से शुरू होकर 21 जून तक मानाया जाएगा। डॉ0 दिनेश चंद्र ने योग क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेते हुए अधिकाधिक जनसहभागिता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को समारोह पूर्वक आयोजित करने के निर्देश दिए। 21 जून को प्रातः 06:00 बजे आयोजित होने वाले दसवें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग स्वयं एवं समाज के लिए रखी गयी है। जनपद में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के सहयोग से जनपद, तहसील, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। उन्हें इस बारे में ससमय अवगत भी करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि योग दिवस पर जनसामान्य की भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने के लिए विभिन्न नेटवर्कों के माध्यम से प्रचार- प्रसार किया जाए। जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी डा.दिनेश चन्द्र ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से होना चाहिए, जिसके लिए हर व्यवस्था समय रहते कर ली जाए। उन्होंने जिला के आम नागरिकों से भी आवाहन किया कि योग दिवस पर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भाग लें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 संजीव मांगलिक, एसपी यातायात सिद्धार्थ वर्मा, आईआईए अध्यक्ष अनूप खन्ना, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉ. राम कृपाल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

शासकीय योजनाओं को पात्रों तक पंहुचाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध :- जिलाधिकारी डा.दिनेश चन्द्र

माटीकला शिल्पियों को प्रशिक्षण देकर बनाया जा रहा आत्मनिर्भर

गौरव सिंघल। सिटी चीफ।
सहारनपुर, राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन जसवन्त सैनी एवं जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र द्वारा उ0प्र0 माटीकला बोर्ड के अन्तर्गत संचालित टूल-किट्स वितरण कार्यक्रम में मण्डल के प्रजापति समाज के 90 लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत चालित चॉक का वितरण एवं भूर्जी समाज के 10 लाभार्थियों को नि:शुल्क पॉपकार्न मशीन का वितरण कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में चयनित परम्परागत कारीगरों में मण्डल के जनपद सहारनपुर के 25 लाभार्थी, मुजफ्फरनगर के 25 लाभार्थी व शामली के 40 लाभार्थियों को चाक वितरित किये गये। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत उद्योगों को पुनर्जीवित कर आगे बढाने में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। माटीकला कौशल विकास योजना के अन्तर्गत माटीकला शिल्पियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा हैं। उन्होंने लाभार्थियों से कहा कि जो टूल किट्स आपको दिए गये है उसका सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से मजबूत बनें एवं अन्य को भी प्रेरित करें।जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण देकर आमजन को हुनरमंद

बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं को पात्रों तक पंहुचाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा करण सिंह पुत्र सुभाष ग्राम गन्देवडा, अरूण कुमार पुत्र रूपचन्द ग्राम सोनाअर्जुनपुर, श्रीमती पूजा रानी पत्नी अमित कुमार अमरदीप कॉलोनी, सहारनपुर, प्रवीण कुमार पुत्र दयाराम ग्राम रणखण्डी, बेजेन्द्र पुत्र राजवीर ग्राम चौरादेव एवं सूरज पुत्र भूषण ग्राम खालापट्टी सहित अन्य सभी लाभार्थियों को अपने हाथों से लाभान्वित किया गया। माटीकला के विशेषज्ञ विकास कुमार प्रजापति हरिद्वार, राजेश, सहारनपुर, गोपाल मुजफ्फरनगर एवं राजवीर सहारनपुर के द्वारा उपस्थित लाभार्थियों को माटीकला उत्पादो की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादो की बिक्री से आय बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन एवं प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, उपायुक्त उद्योग वी0के0 कौशल, जिला अग्रणी प्रबन्धक प्रवीन जमुआर, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड सादबिन अफरोज एवं जिला ग्रामोद्याग अधिकारी सहारनपुर एस0एल अग्रवाल, जिला ग्रामोद्याग अधिकारी मुजफ्फरनगर व शामली तथा लाभार्थीगण उपस्थित रहे।

भाकियू तोमर और फुलास अकबरपुर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर

गांव में बनाई जा रही नई विद्युत लाइन को सडक़ किनारे से सीधे गांव में लाए जाने की मांग की

गौरव सिंघल। सिटी चीफ।
सहारनपुर। देवबंद, भारतीय किसान यूनियन तोमर और फुलास अकबरपुर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर गांव में बनाई जा रही नई विद्युत लाइन को सडक़ किनारे से सीधे गांव में लाए जाने की मांग की है। किसान नेता हाजी अब्बास के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी मांग से सम्बंधित पत्र एसडीएम देवबंद अंकुर वर्मा को सौंपा। पत्र में कहा गया है कि गांव फुलास अकबरपुर में नई विद्युत लाइन का निर्माण हो रहा है। जिसे
गांव के ही एक परिवार के कहने पर प्रधान द्वारा जंगल में घुमाकर गांव में लाया जा रहा है जिससे विभाग का खर्चा भी बढ़ रहा है और पेड़ों की वजह से लाइन के बाधित होने का भी खतरा बढ़ रहा है। ज्ञापन में विद्युत लाइन को सीधे सडक़ पर बंधवाते हुए

गांव लाए जाने की मांग की गई है। इसी गांव से एक लिंक मार्ग गांव सांपला बक्काल को जाता है। इस मार्ग की चौड़ाई को इसके आसपास के चकधारों ने तोड़कर अपने चकों में मिला लिया और रास्ते की चौड़ाई छोटी हो गई। इस रास्ते से स्कूली बच्चे और राहगीर गुजरते हैं। अब रास्ता बिल्कुल संकरा हो जाने के कारण आने-जाने वाले राहगीरों स्कूली बच्चों को बेहद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस लिंक मार्ग से अवैध कब्ज़े को हटाकर इसकी चौड़ाई को पहले के अनुसार कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में मरगूब, शराफत, साजिद, मुस्तकीम, अखलाक, नईम, सलमान, सलीम, अजीम, विकास, जाबिर, रिजवान, सुलेमान, शाबान आदि ग्रामीण शामिल रहे।

आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक उज्जैन के सख्त दिशा निर्देश

शहर व देहात क्षेत्रो के समस्त होटल / लॉज / गेस्ट हाउस / सराय / मुसाफिर खाना / धर्मशाला की बारीकी से चेकिंग

महाकाल पुलिस ने दौराने चेकिंग नियमों के उलंघन करने वाले चार होटल संचालकों/मालिको के विरुद्ध किया प्रकरण दर्ज

आगामी त्योहारों को मद्देनज़र कर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में होटल /लॉज/ गेस्ट हाउस /सराय मुसाफिरखाना/ धर्मशाला/गेस्ट हाउस में ठहरने वालों की जानकारी संबंधित थाने पर प्रस्तुत किए जाने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अनिवार्य किया जाकर आदेशित किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रतिदिन उज्जैन शहर के प्रत्येक थाने में सख्ती से चेकिंग की जा रही हैं। थाना महाकाल पुलिस दौराने चेकिंग क्षेत्र में चार होटल संचालकों द्वारा मुख्य काउंटर में मोबाइल नंबर इस स्पष्ट रूप से अंकित न करने, भस्मारती के संबंध में जानकारी नहीं पायी जाने एवं बोर्ड में मालिक/मैनेजर का नाम/मोबाईल नंबर नहीं होना, फ़ायर सेफ़्टी की कमियां पाई जाने पर होटल संचालकों पर 188 14 सराय अधिनियम 1867 के तहत कार्यवाही की गई। उज्जैन पुलिस द्वारा निर्देशित किया गया कि सर्तकता व सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के साथ -साथ होटल संचालको व प्रबंधको को भी सजकता दर्शाने की आवश्यकता है। एवं हिदायत दी गई कि इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति होने पर उज्जैन पुलिस द्वारा निरंतर चेकिंग कर सख्त कार्यवाही की जावेगी।

तराना में महेश नवमी महोत्सव के अंतर्गत तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ

तराना - माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति दिवस महेश नवमी महोत्सव के अंतर्गत तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यअतिथी गोविन्द जी बाहेती और ओम प्रकाश जी काबरा के व्दारा दिप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर राजेश डोडीया,माहेश्वरी समाज सेवा ट्रस्ट अध्यक्ष दिलीप डोडीया,सचिव संजय बल्दवा,उत्सव समिती से मुकेश लाठी,राकेश लाठी,गौरव काकाणी,अरमान बाहेती,रोहित राठी,महिला मंडल अध्यक्ष कुसुम मंत्री,सचिव सुनन्दा डोडीया,किरण राठी,प्रिती पलौड़,सखी संगठन अध्यक्ष रेणु मुंदडा,सचिव रश्मी लोया उपस्थित थे।

पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में हवाई सेवा से जुड़ेंगे 8 शहर

राजा भोज एयरपोर्ट पर आज सीएम मोहन ने किया शुभारंभ

भोपाल, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गुरुवार को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया. उन्होंने सुबह 9 बजे राजा भोज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया। यह फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी, वहां से सिंगरौली लैंड होगी। मुख्यमंत्री भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू किये जा रहे टिकिट बुकिंग काउंटर का भी शुभारंभ कर यात्रियों को बोर्डिंग पास प्रदान किए। राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मंत्री कृष्णा गौर,धर्मेंद्र लोधी,प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मप्र टूरिज्म बोर्ड के शिव शेखर शुक्ला, प्रबंध संचालक पर्यटन विकास निगम डॉ. इलैयाराजा टी, अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड बिदिशा मुखर्जी उपस्थिति रही। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के आठ शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर मेसर्स जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (फ्लायओला) द्वारा किया जा रहा है।

पायलट, को-पायलट के अलावा छह यात्रियों को लेकर जबलपुर पहुँची पहली फ्लाइट

यात्रियों में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह भी शामिल

जबलपुर से अशोक पंवार सहित चार यात्री जायेगें रीवा । इसके पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमान तल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया । उन्होंने पर्यटन वायु सेवा की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर जबलपुर रवाना किया । जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इस फ्लाइट का वाटर कैनन से किया गया स्वागत । एयरपोर्ट पर पर्यटन वायुसेवा के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया । लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किये गये इस कार्यक्रम में सांसद आशीष दुबे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी इंदु, सन्तोष वरकड़े एवं नीरज सिंह, मध्यप्रदेश तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रवि करण साहू, नगर निगम अध्यक्ष प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, पूर्व विधायक श्रीमती नन्दिनी मरावी एवं अन्य अतिथि मौजूद थे । कार्यक्रम के समापन पर लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह एवं सभी अतिथियों द्वारा फ्लाइट को डुमना एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रीवा रवाना किया गया । जबलपुर से अशोक पंवार एवं भोपाल से सवार तीन यात्री हुए रीवा रवाना ।

विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन

झाबुआ - विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के उपलक्ष में बुधवार को श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति एवं जन साहस संस्था द्वारा बाल श्रम के संबंध में जन जागरूकता हेतु राजवाड़ा से बस स्टैंड तक रैली निकाल कर बाल श्रम के दुष्परिणाम के सम्बंध में जन जागृति फैलाई गई एवं बस स्टैंड पर दुकान स्थापना के संचालकों को बाल श्रम न करने संबंध में जागरूक किया गया तथा अधिनियम के प्रावधानों को विस्तृत रूप से समझाया गया। बस स्टैंड पर पलायन पर जा रहे हैं मजदूर पालकों से भीली भाषा में भी चर्चा कर उन्हें समझाया गया कि अपने साथ बालकों को ना ले जाए इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है एवं बाल श्रम की ओर बालक अग्रसर होता है। अंत में उपस्थित सभी दुकान स्थापना के संचालक एवं पालकों को बाल श्रम न करने/कराने की शपथ दिलाई गई।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कलेक्टर नेहा मीना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान द्वारा स्वयं सीड बॉल का निर्माण कर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश

झाबुआ - प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा जनकल्याण के लिए शुरू किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत झाबुआ विकास खण्ड में 2 जून से लगातार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शासकीय नर्सरी में सीड बाल का निर्माण कर रही है । इसी कड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कलेक्टर नेहा मीना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान ने बुधवार शाम को समूह की महिलाओं के साथ में सीड बॉल का निर्माण किया । महिलाओं द्वारा गीत गाकर सीड बॉल का निर्माण किया जा रहा है। सीड बॉल बनाने में मिट्टी में केचुआ खाद को मिलाया जाता है एवं 1 बॉल में 2, 3 बीज को रख कर बनाया जाता है । सीड बॉल के निर्माण में खमेर, सीताफल, अमलतास एवं इमली के सीड का उपयोग किया गया है। सीड बॉल निर्माण कार्य जिले की सभी ब्लॉक में किया जा रहा है। 12 जून 2024 तक झाबुआ में 2 लाख 81 हजार 747, मेघनगर में 1 लाख 50 हजार , पेटलावद में 1 लाख 50 हजार, रामा में 1 लाख 42 हजार, रानापुर में 1 लाख 40 हजार 850, थांदला में 1 लाख 45 हजार 000, आयुष विभाग द्वारा 10 हजार , वन विभाग द्वारा 20 हजार सीड बॉल का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अभी तक जिले में कुल लगभग 12 लाख से अधिक सीड बॉल का निर्माण किया जा चुका है। जो अभी निरंतर जारी है । जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार/गहरीकरण, चेकडेम/स्टॉपडेम, खेत तालाब, गेबियन संरचना, गली प्लग, कुआ, बावडी, परकोलेशन टेक, रिचार्ज पिट, अंडरग्राउंड डाईक, रूफ वोटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण, नदी/घाट की साफ-सफाई, मंदिर/सार्वजनिक स्थल की साफ-सफाई की जा रही हैं। इस दौरान दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दिनेश वर्मा, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मक्सी पुलिस द्वारा पुर्व में गोवंश का परिवहन एवं व्यापार करने वाले मक्सी क्षेत्र में निवास करने वाले आरोपीयो व उनके बाडे चेक किये गये

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाजापुर श्री यशपाल सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टी. एस. बघेल व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री गोपालसिंह चौहान के निर्देशन में थाना क्षेत्र में पुर्व में गोवंश का परिवहन करने वाले एवं व्यापार करने वाले मक्सी निवासरत आरोपीयो के बाडे एवं मकान पर पतारसी के संबंध में टीम बनाई जाकर थाना प्रभारी निरीक्षक भीमसिंह पटेल द्वारा टीम के साथ गोवंश के अपराधो में पुर्व में लिप्त आरोपीयो के बाडे चेक किये गये तथा घरो को देखा गया तथा आरोपीयो को थाने पर तलब कर उनके डोजियर फार्म भरे गये व प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, गोवंश के अपराधो में पूर्व में लिप्त आरोपीयो के नाम इस प्रकार है 1. अमीर पिता सलीम उम्र 20 साल निवासी काला भाटा मक्सी 2. विष्णु पिता चंदर सिंह लोधी उम्र 27 साल निवासी नई आबादी मक्सी 3. शहजाद पिता सलीम खाँ पिंजारा उम्र 35 साल नि मक्सी 4. इकरार पिता रशीद खाँ पिजांरा निवासी जैन मन्दिर रोड मक्सी 5. युसुफ पिता पीर खाँ उम्र 30 साल निवासी काला भाटा मक्सी 6. राजेश उर्फ कालु पिता फुलसिंह धाकड उम्र 24 साल नि मक्सी 7. राजेश पिता फुलसिंह उम्र 22 साल निवासी काला भाटा मक्सी 8. मो हुसेन पिता काजु खाँ उम्र 42 साल निवासी मक्सी 9. संजय पिता बहादुरसिंह लोधी उम्र 28 साल निवासी नई आबादी मक्सी 10. ललीत पिता लाखन सिंह लोधी उम्र 27 साल निवासी मक्सी 11. अनिल पिता बालचंद लोधी उम्र 32 साल निवासी नई आबादी मक्सी जिला शाजापुर 12. आसिम पिता सलीम खाँ उम्र 33 साल निवासी कालाभाटा मक्सी 13 चेतन पिता मनोहर गुर्जर उम्र 24 साल निवासी हनोती 14 शाहरुख पिता भुरु शाह उम्र 25 साल निवासी काला भाटा मक्सी के है तथा इन आरोपीयो को समझाईश दी गई है, की यदि गोवंश परिवहन करते पाये गये तो मक्सी पुलिस द्वारा शक्ति से कार्यवाही की जावेगी तथा मक्सी पुलिस द्वारा एक टीम भी बनाई गई जिसके द्वारा गोवंश में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. भीमसिंह पटेल, स्कु तेजप्रकाश बौहरे, स्कु आजाद सिंह चौधरी, स्कु संतोष रघुवंशी, स्कु संजय सवनेर, ।ष्ट 164 इन्द्रजीत, ।ष्ट 227 हिरदेश दांगी, ।ष्ट यादवेन्द्रसिंह सेंगर, ।ष्ट 656 राहुल पटेल, ।ष्ट 167 निलेश जामलिया, आर.570 राहुल जाट, आर. 262 जगदीश, आर.62 अरुण सितपरा, आर. 154 दीपक यादव, आर. 220 कुमेरसिंह की सराहनीय भुमिका रही।

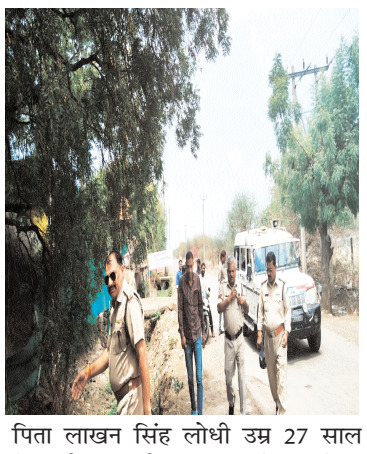

स्मार्ट सिटी में बड़े घोटाले का खुलासा

इंदौर नगर निगम में स्मार्ट सिटी और विद्युत विभाग अधिकारियों ने लूट 24 लाख रूपये प्रतिवर्ष

5 साल में 1 करोड़ 20 लाख लूटे

निगम में स्मार्ट सिटी और विद्युत विभाग मे भ्रष्ट अधिकारियों ने निगम को मेंटेनेंस के नाम पर 75 लाख का चूना अलग से लगाया

इंदौर,इंदौर नगर निगम देश में घोटालों में नम्बर वन हो गया हैं।नगर निगम में भ्रष्टाचार का जमकर बोलबाला हैं। इंदौर नगर निगम में भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का नया इतिहास बनाने की शपथ ले रखी हैं। म.प्र.कांग्रेस कमेटी महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया की नये भ्रष्टाचार का मामला इंदौर नगर निगम स्मार्ट सिटी एंव विद्युत विभाग ने मिलकर किया हैं। इंदौर नगर निगम ने दिल्ली की सूर्या रोशनी लिमिटेड को वर्ष 2019 में 8 हज़ार एलईडी लाईट लगाने का कांट्रेक्ट दिया गया। इसके बाद अतिरिक्त 4 हज़ार एलईडी लाईट लगाने का कांट्रेक्ट बढ़ाया गया।टेंडर की लागत 10 करोड़ थी।कुल 12 हज़ार एलईडी लाईट लगाने का कार्य किया गया था। इंदौर नगर निगम कांट्रेक्ट में सूर्या रोशनी लिमिटेड को 7 सालों तक समस्त 12 हज़ार एलईडी लाइटों को लगाकर समस्त एलईडी लाइटों का मेंटेनेंस सूर्या कंपनी को करना था। लेकिन नगर निगम में स्मार्ट सिटी अधिकारी एंव विद्युत विभाग के अधिकारी आशुतोष शर्मा ने सूर्या रोशनी लिमिटेड को टेंडर देने के बाद मेंटेनेंस का कार्य सूर्या रोशनी लिमिटेड से असंवैधानिक तरीक़े से इंदौर की दम्माणी इलेक्ट्रिकल को दिला दिया। जबकि टेंडर अनुसार मेंटेनेंस का कार्य सूर्या रोशनी लिमिटेड को ही करना था। इसके पश्चात सूर्या रोशनी लिमिटेड ने संपूर्ण एलईडी लाइट लगाकर पेमेंट लेकर दिल्ली रवाना हो गई। जब एलईडी लाइट ख़राब होती हैं तब कंपनी नई लाईट ज़रूर उपलब्ध करा रहीं है।लेकिन स्मार्ट सिटी एंव विद्युत विभाग के अधिकारी इन रिप्लेस एलईडी लाइटों का अन्य जगह उपयोग करके फ़र्ज़ी बिल लगाकर भुगतान मेंटेनेंस के नाम लेते हैं।एंव निगम के अमले के पास मौजूद अन्य एलईडी लाईट को निगम की गाड़ियों से बदला देते हैं। यहाँ निगम के ख़ज़ाने को दो तरह से लूटा गया हैं। इंदौर नगर निगम के टेंडर की शर्तो के अनुसार प्रतिवर्ष मेंटेनेंस का 24 लाख रूपये भुगतान स्मार्ट सिटी द्वारा सूर्या रोशनी लिमिटेड को किया जाता हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारी एंव निगम विद्युत विभाग के अधिकारी दोनों मिलकर डमी कंपनी दम्माणी इलेक्ट्रिकल को मेंटेनेन्स का कार्य कागज़ों पर दिखाकर स्मार्ट सिटी से प्राप्त प्रतिवर्ष 24 लाख रूपये का भुगतान सीधे अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता हैं। 24 लाख प्रतिवर्ष मेंटेनेंस का बजट डमी कंपनी दम्माणी इलेक्ट्रिकल के माध्यम से लूटने के बाद निगम के अधिकारी मेंटेनेंस का कार्य निगम के कर्मचारियों और विद्युत विभाग की गाड़ियों से कराकर इंदौर नगर निगम को लाखों का चूना लगा रहें हैं।निगम की गाड़ी क्रमांक को रंगे हाथ सूर्या की एलईडी लाईट बदलते पकड़ा हैं। सूर्या रोशनी लिमिटेड को मेंटेनेंस के पेटे प्रतिवर्ष दी गई राशि 24 लाख सीधे भ्रष्ट अधिकारियों ने हड़पी हैं।सूर्या रोशनी लिमिटेड से ख़राब हुई एलईडी भी निगम के खर्चे से बदलने का भ्रष्टाचारी खेल जारी हैं। स्मार्ट सिटी में सुनियोजित षड्यंत्र रचकर किये गये भ्रष्टाचार में पूर्व अधिकारी राकेश अखंड एंव वर्तमान अधिकारी सुनील गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इंदौर में भ्रष्ट अधिकारियों की हिम्मत देखिए की मेंटेनेंस का कार्य दम्माणी इलेक्ट्रिक से नहीं कराकर निगम के स्टॉप से मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा हैं। सबूत के तौर पर एक निगम की गाड़ी को साकेत नगर में रंगे हाथ पकड़ा गया।इससे स्पष्ट होता हैं की इंदौर नगर निगम में स्मार्ट सिटी के सुनील गुप्ता एंव विद्युत विभाग के अधिकारी आशुतोष शर्मा एंव लोकेश मेहता अब इंदौर नगर निगम की विद्युत विभाग की गाड़ियों से मेंटेनेंस कराकर जनता के ख़ज़ाने में जमकर चूना लगा रहें हैं। कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव के अनुसार अभी तक 5 साल में लगभग 1 करोड़ 20 लाख की मेंटेनेंस राशि को लूटकर नगर निगम के विद्युत विभाग से मेंटेनेंस कराकर लगभग 75 लाख का चूना इंदौर नगर निगम को लगाया हैं। कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को सारे घोटाले की जानकारी देने के साथ लोकायुक्त एंव आर्थिक अपराध में शिकायत की है। मुख्यमंत्री से माँग की हैं की निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर पर जाँच करके दोषियों के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करायें:- (1) स्मार्ट सिटी निगम अधिकारी राकेश अखंड एंव सुनील गुप्ता के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करके बैंक खातों एंव संपतियों की जाँच करायी जाए। (2) सूर्या रोशनी लिमिटेड से डमी कंपनी दम्माणी इलेक्ट्रिकल को प्रतिवर्ष 24 लाख में से कितना पैसा एकाउन्ट में दिया गया हैं।इसकी जाँच की जाये। (3) इंदौर नगर निगम में विद्युत विभाग की गाड़ियों को रंगे हाथ पकड़ा गया हैं सूर्या रोशनी लिमिटेड का मेंटेनेंस कार्य करते हुए।सबूतों के आधार पर विद्युत विभाग के आशुतोष शर्मा एंव लोकेश मेहता सहित अन्य निगम विद्युत विभाग के ज़िम्मेदार अधिकारियों पर एफ़आइआर दर्ज करके कार्यवाही की जायें। (4) इंदौर नगर निगम विद्युत विभाग द्वारा अवैध रूप से मेंटेनेंस का कार्य पिछले 5 साल से कराने पर दम्माणी इलेक्ट्रिकल सहित निगम के अधिकारियों ने कितना निगम का बजट लूटा हैं।इसकी जानकारी लेकर ऑडिट विभाग द्वारा किये गये भुगतान की जाँच करके निगम अधिकारियों से वापस वसूली की जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव के अनुसार मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेते हुए सख्त कार्यवाही करना चाहिए।

नौकरी गई फिर भी अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी 92 साल की जोआन

इंटरनेशनल डेस्क: 92 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनीं जोआन पेडेन की अनिश्चितता में उलझे भावी उद्यमियों को सलाह है कि जब आप पानी में छलांग लगाते हैं तो डूबने के बारे में नहीं सोच सकते; आपको तैरना ही होगा, हर हाल में सफल ही होना होगा... । फोर्ब्स के अनुसार जोआन की संपत्ति करीब 5,850 करोड़ रुपए है। उनकी मनी मैनेजमेंट फर्म करीब 13.54 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मैनेज कर रही है। 50 के दशक में महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग और फाइनेंस क्षेत्र चुनौती ही थे। संघर्षों से जूझकर कैसे वे शीर्ष पर पहुंचीं डर्बी के कनेक्टिकट में 1931 में जन्म लेने वाली जोआन किशोरावस्था तक इंडोनेशिया में रहीं। अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से फिजिक्स और मैथेमेटिक्स में ड्यूअल बैचलर डिग्री ली। उस दौर में यह किसी महिला के लिए बड़ी उपलब्धि थी। 1950 में न्यू जर्सी में ऑयल रिफाइनरी बनाने वाली कंपनी में बतौर इंजीनियर काम किया। पर छंटनी में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने तत्काल फील्ड बदलकर फाइनेंस से जुड़ने का फैसला लिया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म मेरिल लिंच जॉइन कर ली। पर यहां उन्हें 25त्न कम सैलरी पर रखा गया, क्योंकि उन्हें बॉन्ड और स्टॉक में अंतर पता नहीं था।धीरे-धीरे उनका टैलेंट फाइनेंस वर्ल्ड को पता लगने लगा। इन्वेस्टमेंट काउंसिलिंग फर्म स्कडर, स्टीवंस एंड क्लार्क में वे पहली वुमन पार्टनर बनीं। हालांकि जोआन को बाद में पता चला कि वो फर्म की पहली पसंद नहीं थीं, क्योंकि वो फर्म के पुरुषों के साथ गोल्फ नहीं खेलती थी। इसके लिए उन्हें प्रमोशन से भी वंचित होना पड़ा। उन्होंने नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी के छात्रों से कहा था कि वो खुद को 10 साल बाद वहीं देखना नहीं चाहती थी, जहां से शुरुआत हुई थी। इसलिए 1983 में उन्होंने कमाई से जोड़े 42 लाख रुपए दांव पर लगाकर सहकर्मी सैंड्रा रायगेल के साथ पेडेन एंड रायगेल फर्म की नींव रखी, जो निश्चित आय और वैश्विक बाजारों पर फोकस्ड थी। चार दशक में यह फर्म अमेरिका की बड़ी प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म में से एक बन गई है। साथ ही ये करीब 13.54 लाख करोड़ रुपए का असेट मैनेज कर रही है।

पाकिस्तान ने कहा कि वह भारतीय चुनावों पर टिप्पणी नहीं करेगा

नेशनल डेस्क = पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह हाल ही में संपन्न भारतीय आम चुनाव या भारत के घरेलू मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। विदेश कार्यालय (एफओ) की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान यह टिप्पणी की। जब उनसे भारतीय चुनावों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान आम चुनाव या भारत के घरेलू मामलों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के नेतृत्व के बीच पत्रों का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण पर सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। उन्होंने कहा, राष्ट्र और सरकार के प्रमुखों के लिए अपने समकक्षों को पदभार ग्रहण करने पर बधाई देने की रवायत रही है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बधाई देना उसी संदर्भ में था। आपने भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी देखी होगी। मैं इन संदेशों के संबंध में कोई और स्पष्टीकरण नहीं दूंगी क्योंकि ये संदेश सामान्य प्रकृति के हैं।

अमेरिका: टेक्सास में कंट्री कमिश्नर पद के भारतवंशी उम्मीदवार तरल पटेल गिरफ्तार

न्यूयार्क: भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एवं तीस-वर्षीय नीति विशेषज्ञ एवं टेक्सास के कंट्री कमिश्नर पद के लिए उम्मीदवार तरल पटेल को टेक्सास रेंजर्स ने ऑनलाइन गलत पहचान और मिथ्या प्रस्तुति के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। गलत पहचान का अपराध टेक्सास चुनाव संहिता के तहत श्रेणी-'ए% का अपराध है। फोर्ट बेंड काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का 'पब्लिक इंटीग्रिटी डिवीजन% टेक्सास रेंजर्स के साथ मिलकर प्रीसिंक्ट-तीन कमिश्नर पद के राजनीतिक उम्मीदवार पटेल के खिलाफ शिकायत की जांच कर रहा है। टेक्सास चुनाव संहिता में ऑनलाइन गलत पहचान के लिए थर्ड-डिग्री और पहचान की मिथ्या प्रस्तुति के लिए श्रेणी-ए के अपराध के आरोप मुख्य शिकायतें हैं। जांच अब भी जारी है। पटेल को घोर अपराध के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर के बॉण्ड और चूक के लिए 2,500 अमेरिकी डॉलर के बॉण्ड पर रखा गया है और अगर वह बॉण्ड राशि जमा नहीं कराते तो बृहस्पतिवार सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पटेल की वेबसाइट के अनुसार, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के पास स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राजनीतिक अनुभव है, यहां तक ??कि वर्तमान जो बाइडेन प्रशासन के तहत व्हाइट हाउस के संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। फोर्ट बेंड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि विस्तृत ब्योरा बाद में प्रदान किया जाएगा। पटेल ने पिछले साल सितंबर में अपने खिलाफ रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी द्वारा किए गए नस्लवादी पोस्ट की निंदा करते हुए कुछ ईमेल भेजे थे। हालांकि, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी कमिश्नर एंडी मेयर्स का नाम नहीं लिया था। पटेल के माता-पिता भारत से अमेरिका आकर बस गए थे। पटेल ह्यूस्टन में पले-बढ़े। वह स्थानीय स्कूलों में पढ़े और ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की।

हिजबुल्ला ने इजरायल पर दागे 100 और राकेट कहा- कमांडर की मौत का बदला लेकर रहेंगे

इंटरनेशनल डेस्क: इजरायल अब टू फ्रंट वॉर लड़ने को तैयार है। इजरायल ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हमला किया जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट दागे हैं। इससे इजरायल के कई इलाकों में आग लग गई। ताजा घटनाक्रम में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में और 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे ।पिछले 3 दिनों से लेबनान से उत्तरी इज़राइल में लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं जिसका ढ्ढष्ठस्न ने जवाब दिया है। हिजबुल्लाह ने वादा किया है कि वे इजरायल पर एक मिलियन और रॉकेट दागे जाएँगे। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद इस क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। गाजा में हमास के साथ लड़ रहे इजरायल का संघर्ष अब हिजबुल्लाह के साथ भी बढ़ सकता है। लेबनान में एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या के जवाब में इजरायल पर अपना सबसे भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह ने बुधवार की सुबह इजरायल पर 200 से ज्यादा राकेट दागे। इन हमलों ने चिंता पैदा कर दी है इससे इजरायल को दो मोर्चों पर लड़ना होगा। दोनों का कहना है कि वो लड़ने को तैयार हैं। इजरायली सेना ने बुधवार को पुष्टि की कि उसने हमले में तालेब अब्दुल्ला के साथ हिजबुल्लाह के तीन आतंकियों को मार डाला है। इसके अलावा कहा गया कि लेबनानी क्षेत्र से कम से कम 215 रॉकेट दागे गए। उत्तरी इलाकों में दर्जनों सायरन बजे। सेना ने कहा कि कई रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया। वहीं कई जमीन पर गिरे, जिससे आसपास के इलाकों में आग लग गई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इजरायली फाइटर जेट की ओर से दक्षिणी लेबनान के यारून में रॉकेट लॉन्च साइट पर हमले का फुटेज आया है। अब्दुल्ला को हज अबू तालेब के नाम से भी जाना जाता है। वह कथित तौर पर इजरायल और लितानी नदी के साथ सीमा के बीच की अग्रिम पंक्ति के

कुवैत में आग लगने से मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर वायुसेना का विमान केरल रवाना

नेशनल डेस्क- कुवैत में इमारत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान शुक्रवार तड़के केरल के लिए रवाना हुआ। एक्स पर केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने विकास की पुष्टि की।

स्पेशल विमान राज्य के कोच्चि में उतरेगा।

इस बीच, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जहां विमान उतरेगा, वहां पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तैनात की गईं। गुरुवार को, कुवैत में अधिकारियों ने विदेशी श्रमिकों की एक इमारत में आग लगने की दुखद घटना में मारे गए 45 भारतीयों और तीन फिलिपिनो नागरिकों के शवों की पहचान की। कुवैत ने घटना की तुरंत जांच करने का वादा किया और पीड़ितों के शवों को वापस लाने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। दक्षिणी शहर मंगफ में बुधवार को सात मंजिला इमारत में आग लगने से कम से कम 49 विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए, जहां 196 प्रवासी श्रमिक रह रहे थे। कुवैत फायर फोर्स ने कहा कि घातक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। बल ने एक बयान में कहा कि घटनास्थल और उस इमारत की क्षेत्रीय जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया जहां कल आग लगी थी। इस बीच, कुवैती अधिकारी दक्षिणी कुवैत के मंगफ़ क्षेत्र में विनाशकारी आग की घटना में मारे गए लोगों के शवों का डीएनए परीक्षण कर रहे थे।

पहली विदेश यात्रा के लिए मोदी इटली रवाना, जॉर्जिया मेलोनी से करेंगे मुलाकात

नेशनल डेस्क: नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इटली रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी इटली में चल रही G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इटली रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत यूरोपीय देश रवाना होने से पहले एक बयान में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आउटरीच सत्र में 'ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इटली के अपुलिया क्षेत्र के बोर्गो एग्नाजिया के आलीशान रिसॉर्ट में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले त्ल7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध और गाजा में संघर्ष के मुद्दों के छाये रहने की उम्मीद है। मोदी ने कहा, ''प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर मैं 14 जून को त्ल7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के अपुलिया क्षेत्र की यात्रा कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनकी पहली यात्रा त्ल7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है। मोदी ने कहा, ''आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ''यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन और आगामी G7 शिखर सम्मेलन के परिणामों के बीच अधिक तालमेल लाने और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर होगा।मोदी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ''पिछले साल प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की दो यात्राओं ने हमारे द्विपक्षीय एजेंडे को गति और गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।उन्होंने कहा, ''हम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत एवं भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन से इतर कई द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। उन्होंने कहा, ''मैं शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं से मिलने को लेकर भी उत्सुक हूं। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। इटली त्ल7 (सात देशों के समूह) शिखर सम्मेलन की वर्तमान में अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है। इटली ने अपनी अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की रक्षा करने पर जोर दिया है। इटली के अनुसार, यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध ने उसके सिद्धांतों को कमजोर कर दिया है और दुनिया भर में कई संकटों के साथ बढ़ती अस्थिरता को जन्म दिया है। उसका कहना है कि G7 मध्य पूर्व में संघर्ष और वैश्विक एजेंडे के लिए इसके परिणामों को समान महत्व देगा। रूस को इस समूह में शामिल करने के साथ 1997 और 2013 के बीच इसका विस्तार जी8 के रूप में हुआ। हालांकि, क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2014 में रूस की भागीदारी निलंबित कर दी गई थी। समूह की परंपरा के अनुरूप, कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को अध्यक्षता करने वाले मेजबान राष्ट्र द्वारा शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। भारत के अलावा इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन यह वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

चीनी व रूसी हैकरों ने अमेरिकी विदेश विभाग के 60000 ईमेल चुराए

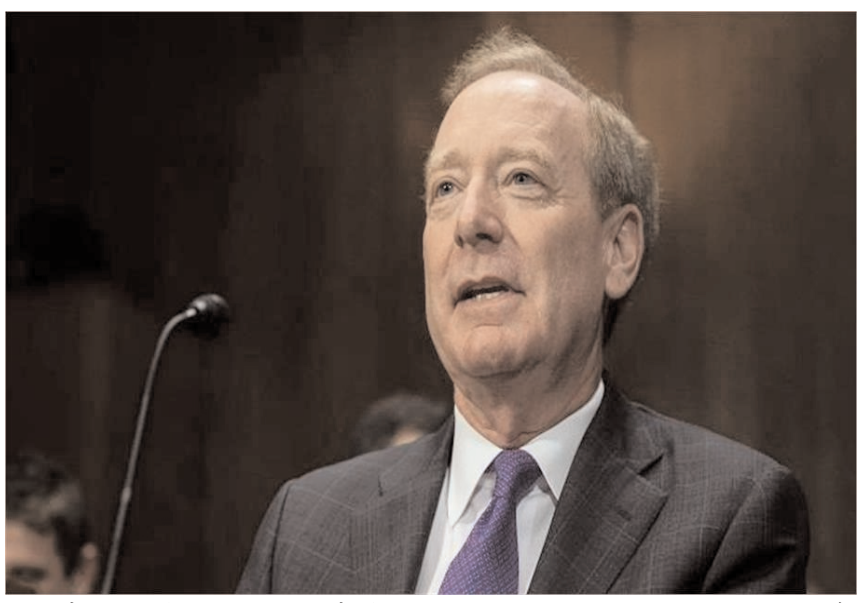

इंटरनेशनल डेस्क: माइक्रोसॉफ्ट ने चीन व रूस के हैकरों द्वारा अमेरिकी विदेश विभाग के ईमेल चुराने के मामले में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अमेरिका ने चीन और रूस में हैकिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया था। चीनी हैकरों द्वारा 60,000 अमेरिकी विदेश विभाग के ईमेल चुराने और रूसी हैकरों द्वारा वरिष्ठ कर्मचारियों के ईमेल की जासूसी करने के बाद ब्रैड स्मिथ माइक्रोसॉफ्ट की सुरक्षा चूक के बारे में गवाही देंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में चीनी हैकिंग के मामले में पारदर्शिता की कमी के लिए माइक्रोसॉफ्ट की आलोचना की गई और इसे रोकने योग्य बताया गया है। कानून निर्माता कंपनी के अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और इन उल्लंघनों के प्रति प्रतिक्रिया की जांच करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ग्रीन ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब माइक्रोसॉफ्ट एक टाले जा सकने वाले साइबर हमले का शिकार हुआ है। Microsoft के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ गुरुवार को कैपिटल हिल में सांसदों को बताएंगे कि कंपनी हर एक मुद्दे के लिए ज़िम्मेदार है, जिसे सरकार के सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में चीन हैक की जांच करते समय उजागर किया था । राष्ट्र-राज्य साइबर हमलों की एक श्रृंखला के बाद अमेरिकी सांसदों, प्रशासन के अधिकारियों और नियामकों ने तकनीकी दिग्गज की अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने की क्षमता पर भरोसा खोना शुरू कर दिया है। स्द्बष्ह्म्शह्यशद्घह्ल ने पिछले साल दो उल्लेखनीय राष्ट्र-राज्य साइबर हमलों का सामना किया है, जिसने संघीय एजेंसियों के संचार को खतरे में डाल दिया है। Microsoft ने पिछले जुलाई में खुलासा किया था कि चीन समर्थित हैकिंग समूह ने संघीय कार्यालयों सहित कई संगठनों के ईमेल खातों में सेंध लगाई थी। वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और कई राज्य अधिकारी प्रभावित हुए।साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में कहा कि रूसी खुफिया हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट में सेंध लगाने के बाद कई संघीय एजेंसियों के ईमेल भी चुरा लिए। इन घटनाओं के बाद से, माइक्रोसॉफ्ट को वाशिंगटन में सांसदों और प्रतिस्पर्धियों से कड़ी जांच का सामना करना पड़ा है। साइबर सुरक्षा समीक्षा बोर्ड ने अप्रैल की एक रिपोर्ट में कहा कि चीनी जासूसी अभियान, विशेष रूप से, रोका जा सकता था और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सीनेटर पेंटागन की कथित योजनाओं के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों के अपने सूट को अपने शून्य-विश्वास संक्रमण के हिस्से के रूप में अपग्रेड करने की योजना है। और उत्सुक प्रतिस्पर्धी माइक्रोसॉफ्ट के सरकारी ग्राहकों को लुभाने के लिए अभियान चला रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट संघीय सुरक्षा नेताओं और उनकी टीमों को सुरक्षा सिद्धांतों के एक नए सेट के बारे में जानकारी दे रहा है, जिसे वह आंतरिक रूप से लागू कर रहा है, जिसे सिक्योर फ्यूचर इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता है। यह योजना साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए अधिकारियों के वेतन को जोड़ती है और टीमों से तेजी से उत्पाद विकास पर सुरक्षा निवेश को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569